सुविचार

आज हज़ारों में हैं
कल लाखो में
जुड़ेंगे तुम
दूरबीन लगाकर
देखनाजब हम
आसमान में
उड़ेंगें..!!

साप्ताहिक

युवा प्रदेश

Freedom Of Speech

RNI. NO. MPHIN/2015/76299

संपादक-नागेश नरवरिया

वर्ष 7, अंक-44 | www.yuvapradesh.in | भोपाल, शुक्रवार 9 दिसंबर 2022 | ypnews24@gmail.com | पृष्ठ -8 | मूल्य 2 रुपये

Mother's Basket
Kitchen Herbs & Spices
Swad jo pahuche dil tak

क्या है विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण जानिए मौलिक अधिकार सीरीज/Fundamental Right....

भारतीय संविधान अधिनियम,1950 के अनुच्छेद 14 से 18 तक समता(समानता) का अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, समानता से अर्थ है की भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति कानून के समक्ष

समान है कानून सभी के साथ समान न्यायालय करेगा अर्थात एक आरोपी को भी आपने बचाव के लिए उतना ही अधिकार होगा जितना वादी को आरोप सिद्ध करने का होता है। संविधान में समानता का अधिकार विधि के समक्ष होगा और हमारा देश विधि द्वारा ही चलता है,जानते हैं आज हम विधिक संरक्षण एवं विधिक समानता क्या है?

भारतीय संविधान अधिनियम,1950 के अनुच्छेद 14 की परिभाषा-?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 समता का सामान्य नियम बताता है जो व्यक्तियों के बीच अयुक्तियुक्त विभेद को खत्म करता है। इस अनुच्छेद में बताया गया है की सभी नागरिक विधि के समक्ष समान है एवं सभी को विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। साधारण शब्दों में कहे तो अनुच्छेद 14 कानून के सामने सभी नागरिकों को समान मानता है एवं सभी को कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा अर्थात विधि के उल्लंघन पर जो दण्ड एक आम नागरिक जो मिलता है वो ही दण्ड देश के राष्टपति को भी मिलेगा। हमारा देश भारतीय संविधान एवं विधि के अनुसार चलता है एवं कानून(विधि) के उल्लंघन पर ही नागरिकों को न्यायालय द्वारा दण्ड दिया जाता है इस प्रकार विधि के समक्ष सब सभी को समानता एवं विधि से संरक्षण प्राप्त है।

लेखक बीआर अहिरवार(पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665

गुजरात में भाजपा ने जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़े

सबसे अधिक वोट सबसे अधिक सीटें मिलीं, लगातार सातवीं बार जीत के रिकॉर्ड को छुआ

एजेंसी/गुजरात। गुजरात में भाजपा ने 52 फीसदी वोट और 156 सीट हासिल करके इतिहास रच दिया। राज्य में अब तक के चुनावों में इतना जबरदस्त बहुमत किसी भी दल को नहीं मिला। इससे पहले कांग्रेस ने 1985 में माधव सिंह सोलंकी की अगुआई में 149 विधानसभा सीटें जीती थीं। वहीं, 2002 में नरेंद्र मोदी के ष्टरूरहते भाजपा को 127 सीटें मिली थीं। भाजपा ने दोनों रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसके साथ ही लगातार एक दल की सातवीं जीत के रिकॉर्ड को भी छू लिया है। पहले यह कारनामा बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कर चुकी है। वह 1977 से 2011 तक सत्ता में रही और सात विधानसभा चुनाव जीती। भाजपा की इस जीत के पीछे हिंदुत्व, विकास का पैकेज और बाहरी बनाम भीतरी का मुद्दा भारी पड़ा। केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल की तरह जनता से मुफ्त योजनाओं का वादा किया। लेकिन भाजपा ने इसे गुजरात के स्वाभिमान से जोड़ दिया और जनता से नकारने की अपील की, जो कामयाब रही।

भाजपा 156 सीटें जीती, कांग्रेस 17 पर सिमटी

गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में से भाजपा ने 156 सीटें जीती। उसे 2017 के मुकाबले 58 सीटों का फायदा हुआ। वहीं, कांग्रेस को सबसे ज्यादा 60 सीटों का नुकसान हुआ। पार्टी ने पिछली बार 77 सीटें जीती थीं। इस बार उसे 17 सीटें ही मिलीं। पहली बार गुजरात चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी पांच सीटें जीतने में सफल हुई। निर्दलीय और अन्य कैंडिडेट्स ने गुजरात में 4 सीटें जीतीं। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव प्रचार के दौरान ह्रूमोदी ने कहा था- नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेंगे। चुनाव नतीजों में बिल्कुल यही नजर आ रहा है।

मोदी बोले- गुजरात की जन-शक्ति के आगे सिर झुकाता हूं

गुजरात में क्ष्क्ककी विराट जीत के बाद क्करूमोदी ने गुजरात की जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा- गुजरात आपका धन्यवाद। ऐसे नतीजे देखकर मैं अभिभूत हूं। लोगों ने विकास की राजनीति को अपना आशीर्वाद दिया है और यह भी बता दिया है कि वे इस विकास को और भी तेजी से जारी रखना चाहते हैं। मैं गुजरात की जन-शक्ति के आगे सिर झुकाता हूं। उन्होंने कहा कि मैं बड़े-बड़े एक्सपर्ट को याद दिलाना चाहता हूं कि विकसित गुजरात से विकसित भारत का निर्माण होगा। गुजरात के नतीजों ने सिद्ध कर दिया है कि देश के सामने जब कोई चुनौती होती है तो जनता का भरोसा भाजपा पर होता है।

12 दिसंबर को गांधीनगर में CM पद की शपथ लेंगे पटेल

गुजरात में गुरुवार सुबह 8 बजे से पहले आधे घंटे में पोस्टल बैलेट्स की गिनती के बाद श्व्ङ्करूसे काउंटिंग शुरू हुई थी। गुजरात भाजपा प्रमुख ष्टक्रपाटिल ने बताया कि 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री पद शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने की हरदा जिले की वर्चुअल समीक्षा

शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में जनता का संतोष हमारी प्राथमिकता- मुख्यमंत्री श्री चौहान

- निर्माण-कार्यों की गुणवत्ता के प्रति सतर्क रहना आवश्यक
- जन-प्रतिनिधि और अधिकारी-कर्मचारी मिलकर बनाएंगे हरदा को आदर्श जिला

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जन-कल्याणकारी योजनाओं और विकास गतिविधियों का संचालन पारदर्शिता के साथ समय-सीमा में किया जाए। निर्माण-कार्यों में गुणवत्ता के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है। शासकीय गतिविधियों के क्रियान्वयन में अधिकारी-कर्मचारियों के साथ जन-प्रतिनिधि भी सक्रिय भूमिका निभाएँ और जन-सामान्य से निरंतर संवाद में रहें। शासकीय कार्यों के प्रति जनता में संतोष का भाव सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान हरदा जिले में संचालित जन-कल्याणकारी योजनाओं, विकास गतिविधियों और कानून-व्यवस्था की निवास कार्यालय से वर्चुअली समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जन-प्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। जल संसाधन तथा हरदा जिले के प्रभारी मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, सांसद श्री दुर्गादास उईके, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस सहित विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिव, कलेक्टर हरदा तथा अन्य अधिकारी हरदा से वर्चुअली जुड़े। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हरदा जिले को सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में आदर्श जिला बनाना है। जिले में शत-प्रतिशत सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। जल ज्योर्तिर्मय शिविरों का आयोजन, साइबर सखी योजना, गोंडी एवं कोरकू में पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करने, क्लस्टर क्रेडिट केम्प के नवाचार सराहनीय है। आँगनवाड़ियों का संचालन संतोषजनक है। अधिकारी-कर्मचारी तथा जन-प्रतिनिधि समन्वित रूप से प्रयास करते हुए जिले में ऐसी प्रक्रियाएँ स्थापित करें जिसका अन्य जिले भी अनुसरण करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जल जीवन मिशन में संचालित गतिविधियों की प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। खोदी गई सड़कों के रि-स्टोरेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए तथा पानी की संतोषजनक आपूर्ति सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मिशन के कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह सुनिश्चित करें कि प्रधानमंत्री आवास योजना में आवासों का निर्माण समय पर हो और किश्त जारी करने में बेईमानी या भ्रष्टाचार न हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संभागायुक्त नर्मदापुरम को हरदा जिले में ग्रामीण यांत्रिकी विभाग की जाँच के निर्देश दिए।

8 सवालों से समझें पूरे गुजरात चुनाव का गणित

भाजपा ने दिया विकास-हिंदुत्व का पैकेज आप ने विपक्षी वोट को ही दो-फाड़ किया

अहमदाबाद। गुजरात में भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की सुनामी के अलावा अगर कोई बड़ा कारण है तो वह है पूरे चुनाव को बाहरी बनाम भीतरी करने की भाजपा की कामयाब रणनीति। साथ ही भाजपा ने गुजरात मॉडल के रूप में हिंदुत्व और विकास का ऐसा पैकेज लोगों को दिया कि वोट देने वाले आधे से अधिक लोगों ने सिर्फ कमल का बटन ही दबाया। आप ने यहां मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की बजाय सीधे कांग्रेस के वोट को दो-फाड़ कर दिया। इस कारण भाजपा ने गुजरात में सीट और वोट दोनों का एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर दिया। इस रिजल्ट से उठने वाले 8 सवालों के जरिए समझते हैं गुजरात चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के क्या कारण रहे। साथ ही भविष्य की राजनीति को ये चुनाव कितना और कैसे प्रभावित करेगा?

1. भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत का सबसे बड़ा कारण क्या है?

मोदी की लहर नहीं, सुनामी। इसका मुख्य कारण रहा लोगों में बाहरी बनाम भीतरी का मुद्दा। कांग्रेस कोई लोकल चेहरा नहीं खड़ा कर पाई और क्कअरविंद केजरीवाल के फेस पर ही गुजरात गई। इसीलिए पिछली बार से कम वोटिंग के बावजूद भाजपा को ऐतिहासिक वोट (52.5त्र) और सीट (156) मिले।

2. क्या मोदी के दम पर इतनी बड़ी जीत संभव है?

2014 में मोदी पीएम बने। गुजराती आज भी मानते हैं कि मोदी गुजरात में ही हैं। उन्हें वह अपने प्राइड से जोड़कर देखता है। गुजरातियों को लगता है कि मोदी ने गुजरात आकर कह दिया है तो अब इसके बाद किसी की बात सुनने की जरूरत नहीं। इस बार मोदी ने अहमदाबाद में सबसे लंबा 54 किलोमीटर का रोड शो, तीन और रोड शो, साथ ही 31 सभाएं कीं। 95त्र इलाकों में बीजेपी को जीत मिली है, लेकिन ये कहना गलत होगा कि ये सिर्फ मोदी के दम पर है।

3. फिर भाजपा की सबसे बड़ी रणनीति क्या रही?

हिंदुत्व और विकास का पैकेज। सभी जानते हैं कि हिंदुत्व की प्रयोगशाला गुजरात से शुरू हुई थी। 2002 के गोधरा दंगों के बाद भाजपा ने हिंदुत्व के मुद्दे पर 127 सीटों के साथ ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। फिर 2003 में वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत की।

4. गुजरात में क्कका दिल्ली मॉडल क्यों नहीं चला?

बिजली बिल माफ, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज और मुफ्त अच्छी शिक्षा_क्क के दिल्ली मॉडल का मुख्य हिस्सा है। गुजरातियों को भाजपा ये समझाने में कामयाब रही कि मुफ्त का कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भाजपा ने दिल्ली मॉडल के मुकाबले गुजरात मॉडल की वकालत की और उसे गुजरात प्राइड से जोड़ दिया। यानी गुजरात मॉडल को गुजरातियों का मॉडल बना दिया।

5. क्या क्ककी पूरी रणनीति फेल हो गई?

नहीं, ऐसा नहीं है।क्ककी रणनीति का एक मुख्य हिस्सा था कि गुजरात में चुनाव के जरिए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करना। करीब 13त्र वोट मिलने के साथ उसे ये दर्जा मिल जाएगा।

आधार का उपयोग बढ़ाने एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के क्रियान्वयन की निगरानी समिति का पुनर्गठन

भोपाल। आधार का उपयोग बढ़ाने एवं प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पूर्व में (2016 में) गठित समिति का पुनर्गठन किया है। समिति में प्रमुख सचिव/सचिव खाद्य-नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, स्कूल शिक्षा, महिला-बाल विकास, जनगणना निदेशक, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के प्रतिनिधि, राज्य नोडल अधिकारी ई-गवर्नेंस, उप-महानिदेशक यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम सदस्य और प्रमुख सचिव/सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सदस्य सचिव होंगे। भारतीय यूनिक पहचान प्राधिकरण की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन एवं नागरिकों के रजिस्ट्रेशन से संबंधित कार्यों के क्रियान्वयन के लिए पुनर्गठित समिति द्वारा आधार नामांकन और अद्यतनीकरण पारिस्थितिकी-तंत्र के कार्यान्वयन की निगरानी, आधार पहचान प्लेटफॉर्म के उपयोग की समीक्षा, नागरिक शिकायतों के निवारण की प्रगति की निगरानी, आधार पारिस्थितिकी-तंत्र के भागीदार की सूचना सुरक्षा और गोपनीयता प्रथाओं की समीक्षा, जिला स्तरीय आधार निगरानी समितियों का पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन और राज्य सरकार के पोर्टल की कार्य-प्रणाली की निगरानी के कार्य किये जायेंगे।

एक सिपाही का त्याग

लहू तूने लाल-लाल,कुमकुम सा गुलाल।
जय-जय माता भारती के,भाल पे सजा दिया।
माई का दुलार भूल,बापू का वो प्यार भूल।
बहन की राखी को भी,तूने विसरा दिया।
पत्नी की भीनी मुस्कान को भी,रख ताक।
सारी सुख सुविधा को,तूने ठुकरा दिया।
मातृभूमि ऋण को,चुकाया तूने काट शीश।
भारती की आरती के थाल में सजा दिया।

कवि आशीष चौहान
बाड़ी जिला रायसेन
मध्य प्रदेश।

बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष में गैरतगंज में कैंडल मार्च निकाला

रायसेन। दिनांक 6 दिसंबर 2022 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष में भीम आर्मी रायसेन जिला संयोजक जीतेन्द्र मूलनिवासी के आदेशानुसार भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला सह. संयोजक नीलेश चौधरी के नेतृत्व में तहसील गैरतगंज में कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण से प्रारंभ होकर अंबेडकर पार्क टेकापार जाकर समाप्त हुआ। सभी लोगों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि दी और बाबा साहब के विचारो को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। एवं बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे ओर सविधान अमर रहे के नारे लगाए। इस पुष्पांजलि कार्यक्रम में मुख तौर पर ग्राम सर्रा, हरदोट, खजूरिया, घाना, गैरतपुर एवं नगर के अन्य गांवों से भीम आर्मी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित हुए। उपस्थित लोगों में मुख्य तौर पर नीलेश चौधरी- भीम आर्मी जिला सह संयोजक रायसेन। धर्मेंद्र चौधरी - ब्लॉक संयोजक भीम आर्मी गैरतगंज। रामसेवक अहिरवार जी (शिक्षक)। खुमान सिंह अहिरवार शिवराज सिंह अहिरवार (अतिथि शिक्षक) मिश्री लाल अहिरवार अध्यक्ष ग्राम सर्रा, रामसिंह अहिरवार कमलेश अहिरवार। शुभम अहिरवार ,लक्ष्मीनारायण, रोहित ,गोविंद ,राजा ,पूरन ,सिंह ,दीपक, नितेश, एवं अन्य भीम आर्मी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस मना कर बाबा साहेब को याद किया

उदयपुरा। उदयपुरा तहसील के गाँव बनखेडी में दिन मंगल वार को संध्या के समय वोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस मना कर बाबा साहेब को याद किया. कार्यक्रम का आयोजन लक्ष्मण सिंह चौधरी शिक्षक द्वारा किया गया.कार्यक्रम का शुभारंभ पूर्व सरपंच श्री भैया लाल जी ने दीप प्रज्ज्वलित एवं पुष्प माला पहनाकर किया.कार्यक्रम में उपस्थित मुन ना लाल, क्रस, नरेश, उमेश, अकित, रामकुमार, राकेश, साबरी, सूरज, रूपेश, संदीप, गंगा राम, कली बाई, रामबती बाई, माया, शिवानी, फूल सिंह आदि लोगों ने बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया।

अजाक्स कार्यालय सतना में परम् पूज्य् बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया

सतना। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति/ जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अजाक्स जिला इकाई सतना द्वारा अजाक्स कार्यालय आर- 102, सिविल लाइन कोठी रोड सतना में आज दिनांक 6/12 /2022 को परम पूज्य् बोधिसत्व बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया अजाक्स के जिलाध्यक्ष माननीय, रामकलेश साकेत जी, के द्वारा सर्वप्रथम बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में अजाक्स सतना कोचिंग सेंटर के छात्र-छात्राएं एवं टीचर उपस्थित रहे।

आत्मा का ज्ञान ही सत्यस्वरूप हैः सुकरात

भोपाल। संपूर्ण विश्व में समय-समय पर अनेक महान पुरुषों व गुरुओं ने मानव जाति के उत्थान व मार्गदर्शन हेतु अवतरण लिया सुकरात भी उन्हीं में से एक हैं। उनके विचार व आत्मज्ञान सहजयोग के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। अपने को जानो ।आत्मा का ज्ञान ही सत्यस्वरुप है। उसको पा लेना ही मनुष्य जीवन का सबसे बडा पुण्य है द्य और उसके प्रति अज्ञान की अवस्था ही सबसे बड़ा पाप है। सुकरात ग्रीक देश के उच्च कोटी के तत्वज्ञ थे। साधक को सत्य तक पहुँचाने के लिए उन्होंने एक अभिनव प्रश्नोत्तर पद्धति खोज निकाली थी। वो अपने सभी शिष्यों के साथ मित्रों जैसा व्यवहार करते थे। उनका बाह्य व्यक्तित्व बहुत ज्यादा आकर्षक नहीं था, कुरूप था। एक बार वो अपने आप को आईने में निहार रहे थे। तब उनका शिष्य बोला, गुरुदेव ,आप आईने में क्या देख रहे है ? तब वे बोले, सभी ने अपने-आपको हर दिन आईने में देखना चाहिये, चाहे वो व्यक्ति सुंदर हो या कुरुप। जब एक बदसूरत आदमी आईने में देखेगा तो वो अपनी बदसूरती से छुटकारा पाकर समाज से सराहना पाने के लिये अच्छे कर्म करेगा, उसकी कुरूपता उसे सदैव अपनी आत्मा की और धकेलेगी। यहाँ ये ध्यान मे रखिये की हमारे अंदर के सभी षड रिपू जैसे -क्रोध- काम अहंकार, मोह, लोभ और माया ही हमारी कुरूपता है और जब कोई सुंदर आदमी आईने मे देखेगा तो वह, भगवान की इस सुंदर कलाकृति पर खुश होगा।

भोपाल के नीलम पार्क में डा. आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर छात्रों ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी

भोपाल। भोपाल के नीलम पार्क में डा. आंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर छात्रों ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि देते हुए सभा की शुरुआत मुख्य वक्ता के रूप में साथी अजय ने अपना वक्तव्य दिया उन्होंने संविधान पर हो रहे हमले शिक्षा का जिस तरीके से निजी करण किया जा रहा है नई शिक्षा नीति के माध्यम से गरीब मजदूर दलित आदिवासियों के बच्चों को शिक्षा से बाहर करने का रास्ता सरकार की ओर से बनाया जा रहा है शिक्षा को गैर वैज्ञानिक गैर तार्किक बनाकर लोगों को आज विकलांगता की तरफ धकेला जा रहा है उन्होंने बताया कि बाबासाहेब के सपनों का भारत बनाने के लिए संविधान को बचाना जरूरी है संविधानिक मुल्यों की रक्षा कर आधुनिक भारत का निर्माण किया जा सकता है जिसमें छुआछूत अशिक्षा बेरोजगारी ना हो जिसके लिए हमें सतत संघर्ष को तेज करना होगा और संविधान को बचाने के लिए नई शिक्षा नीति को वापस कराने के लिए हमें संगठन को मजबूत करना होगा ताकि हम बाबासाहेब के सपने को साकार कर सकें उनका सपना रहा है शिक्षित बनो संगठित रहो और संघर्ष करें इन्हीं शब्दों के साथ साथी अजय ने अपना वक्तव्य समाप्त किया। इसी कड़ी में जिले की ओर से दीपक पासवान ने अपनी बात रखते हुए नई शिक्षा नीति के माध्यम से छात्र-छात्राओं को शिक्षा से बेदखल किया जा रहा हैं स्कूल कॉलेज शैक्षणिक संस्थानों का निजीकरण किया जा रहा है हमें शिक्षा से इस बेदखली की नई शिक्षा नीति को रोकना होगा इसके लिये हमें संघर्ष को और मजबूत बनाना होगा इन्हीं शब्दों के साथ साथी दीपक ने अपनी बात समाप्त की वक्तव्यों की श्रंखला में साथी सोनू अहिरवार ने भी डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष और उनके विचारों पर अपनी बात रखी इसी के साथ साथी जितेंद्र ने भी अपना संबोधन दिया सभा का संचालन साथी संदीप ने किया और कार्यक्रम की अध्यक्षता संदीप मांडरे और प्रणय ने की अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ सभा में उपस्थिति सभी साथियों को धन्यवाद देते हुए सभा की समाप्ति की घोषणा की गई।

जमीन-भू-अर्जन के लिए ग्रामसभा की सहमति जरूरी

पेसा एक्ट के प्रति जागरूक करने छात्र-छात्राओं व समितियों ने निकाली रैली

शहडोल। कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य के मार्गदर्शन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी अधिकारी जिला पंचायत श्री हिमांशु चंद्र के निर्देशन एवं जन अभियान परिषद के जिला समन्वयक श्री विवेक पाण्डेय की अगुवाई में आज प्रस्फुटन समिति जरवाही एवं पकरिया, नवांकुर संस्था मातृ शक्ति महिला मण्डल समिति एवं छात्र-छात्राओं द्वारा ग्राम पंचायत पकरिया में पेसा एक्ट के प्रति लोगों को जागरूक करने के उददेश्य से जागरूकता रैली निकाली गई। जागरूकता रैली में बताया गया कि पेसा एक्ट पेसा एक्ट यानि पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए पारंपरिक ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिनियमित एक कानून है, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों की ग्रामसभा को सशक्त बनाया गया है।

बाजार-मेलों का प्रबंधन ग्रामसभा करेगी तो ग्राम विकास की कार्ययोजना भी वही बनाएगी। जनजाति वर्ग के व्यक्ति की भूमि पर किसी गैर जनजाति व्यक्ति ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है तो ग्रामसभा को उसे हटवाकर मूल व्यक्ति को दिलाने का अधिकार दिया गया है। ग्रामसभा की सहमति के बिना अनुसूचित क्षेत्रों में नई शराब दुकान नहीं खुलेगी। भूमि अधिग्रहण के पहले भी सहमति लेनी होगी। स्थानीय पुलिस स्टेशन में ग्राम के व्यक्ति से संबंधित कोई भी प्राथमिक सूचना दर्ज होती है तो इसके सूचना ग्रामसभा को देनी होगी। जमीन-भू-अर्जन के लिए ग्रामसभा की सहमति जरूरी जैसे अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया गया। इस अवसर पर ब्लॉक समन्वयक जन अभियान परिषद श्री आशीष मुखर्जी, अर्जुन सोनी सांसद प्रतिनिधि, मीनू जैन अजय पांडे, लक्ष्मी सोनी, किरण श्रीवास, बद्री प्रसाद साहू प्रधानाध्यापक शिक्षक अर्चना त्रिपाठी, सरिता पेंड्राम आरती बर्मन पुरुषोत्तम सोनी डबल सिंह, राम सिंह, रोहिणी केवट, हीरा सिंह, जगदीश सिंह, राम पांडे बबलू, सिंह दुर्गा, केवट रमेश,केवट, राजेश केवट सहित छात्र-छात्राएं एवं ग्रामीणजन साथ रहें।

आवश्यकता

युवा प्रदेश नेटवर्क

मध्यप्रदेश के सभी जिले व तहसीलों में संवाददाता नियुक्त किये जाने है। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें।

युवा प्रदेश नेटवर्क,
प्रधान संपादक-नागेश नरवरिया
मो.- 9425156055-9755364204

ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का वार्षिक अधिवेशन पूरी में संपन्न

नगर संवाददाता

बुढार। गंगाधर चौधरी द्वारा द्य ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन का वार्षिक अधिवेशन पूरीमैं आयोजित किया गया रेली का प्रारंभ बीएनआर क्लब से प्रारंभ होकर पूरी शहर का भ्रमण करते हुए मुख्य मार्ग से होते हुए पूरी रेलवे स्टेशन के समक्ष सभा में परिवर्तित हुआ। इस ऐतिहासिक रैली, शोभा यात्रा का पुरी के चौक,चौराहों पर फूलों की वर्षा कर ऐतिहासिक स्वागत किया,जो देखते बन रहा था। रैली में हिंदुस्तान के 17 जोन एवं 7 उत्पादन इकाइयों के लगभग 50,हजार महिला एवं पुरुष सदस्यों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई। शोभा यात्रा, रैली, पूरी रेलवे स्टेशन पर पहुंची जहां। खुला सत्र के माध्यम से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। खुला अधिवेशन के मंच पर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के अध्यक्ष कन्हैया, महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा, रेलवे बोर्ड की मेंबर अलका अरोरा मिश्रा, ईस्ट कोस्ट रेलवे के महाप्रबंधक रूप नारायण सोनकर,डीआरएम रिंकेस राय, महिला विंग की राष्ट्रीय कन्वीनर प्रमिला सिंह,ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की मंत्री चंपा वर्मा, सहित 17 जोन के महामंत्री एवं अध्यक्षों ने भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में बिलासपुर जोन के महामंत्री मनोज बेहरा, बिलासपुर डिवीजन के डिविजनल कोऑर्डिनेटर सी.नवीन कुमार, राजकिशोर चौधरी,के.अमर कुमार, के.के मोहती,एस.

बंदोपाध्याय, संदीप चंद्रा, मुकेश कुमार,यूके बारीक, दीपक कुमार, राजकुमार, अनंत कुमार, संजय दास, राजेश डोंगरे, गिरजा शंकर पुरी, सहीत बिलासपुर जोन के तीनों डिवीजन से हजारों कार्यकर्ता ने भाग लिया। इस अवसर पर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने खुला अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि रेल का निजीकरण किसी भी सूरत पर बर्दाश्त नहीं है। सरकार से 1974 के बाद कभी आर पार की लड़ाई नहीं हुई हैं,तो सरकार हमें पंगु न समझे।दोस्ताना व्यवहार के माध्यम से जो हमारी मांगे हैं वह मांगे सरकार पूरा करें। पुरानी पेंशन स्कीम को पुनः बहाल करें। आज हिंदुस्तान के रेलवे में 7~50 लाख गैर पेंशन कर्मचारी, समस्त भारत के एजेंसियों के 20 लाख कर्मचारी सहित पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों के करोड़ों कर्मचारी पेंशन से महरूम हो रहे हैं। पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी है सरकार उनसे उनकी लाठी को ना छीने और छीनी हुई लाठी को पेंशन के रूप में वापस करें। रेल कर्मचारियों ने कोविड-19 के समय जब सब लोग घरों में बंद थे, रेल कर्मचारी और अधिकारियों ने बढ़-चढ़कर काम किया। ऑक्सीजन गैस, फल, दूध आवश्यक वस्तुओं को जनसामान्य लोगों के पास रेल परिवहन के माध्यम से पहुंचाया,और माल रेलगाड़ियों का संचालन किया। जिसके कारण लगभग देश के विभिन्न जोनों के लगभग 3 हजार रेल कर्मचारी शहीद हुए। खुला अधिवेशन में शिव गोपाल मिश्रा ने उपस्थित सदस्यों का अभिवादन करते हुए कहा कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की आप सब ताकत है जिस कारण सरकार या मंत्रालय हम को झुका नहीं सकता है। आने वाले समय में निश्चित रूप से आप सभी को इस अधिवेशन का लाभ मिलेगा,और जो हमारी मांग है की पुरानी पेंशन को पुनः बहाल कर दिया जाए सरकार पूरा करे।उन्होंने कहा कि ट्रैकमैन साथियों के लिए अंतिम स्लैब 24सौ 28सौ ना होकर 42 सौ तक कैसे पहुंचे इस विषय में हम जिम्मेदारी पूर्वक कार्यवाही में लगे हैं कि रास्ता कहां से बने। सभी विभागीय कर्मचारियों को डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता। 1974 की हड़ताल पर हम कब तक जीवित रहेंगे, यदि जरूरत पड़ा तो हम हड़ताल से पीछे नहीं हटेंगे।ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन संघर्ष की पर्याय है, संघर्ष हमारे खून में है। हम संघर्ष से घबराने वाले नहीं हम संघर्ष से रास्ता बनाने वाले लोग हैं। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने आश्वस्त किया है कि जहां पर रेल कर्मचारी अपने कार्यों को दक्षता और कार्यकुशलता के साथ करते रहेंगे उन स्थानों पर कभी भी निजी करण या निगमीकरण नहीं किया जाएगा। खुला अधिवेशन को ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया एवं मंच पर उपस्थित अतिथियों ने भी संबोधित किया। उक्त आशय की जानकारी देते हुए श्रमिक यूनियन ब्रांच बुढार अनूपपुर अध्यक्ष नसीर राजा ने बताया खुला सत्र में सभी का स्वागत ईस्ट कोस्ट रेलवे श्रमिक यूनियन के महामंत्री पीके पाठसानी ने किया।

नारी सशक्तिकरण के लिए NFT MMA BJJ और सुनहरा वेलफेयर सोसायटी करवा रहे है नि :शुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण

भोपाल। बावडिया कला में एक निशुल्क आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करवा रहे हे जो 3 दिन तक चलेगा जिसमे समस्त प्रशिक्षण एवम सेमिनार हस्त्रञ्ज स्रू क्च्छ्छ के माध्यम से किया जायेगा इस शिविर में महिलाओं को आत्म रक्षा की तकनीक को सिखाया जाएगा ,प्रशिक्षण पश्चात सबके लिए एक फाइट ड्रिल का आयोजन किया जाएगा जिसमें जीतने वाली प्रतियोगी को ट्रॉफी ओर सर्टिफिकेट प्रदान किए जायेंगे ! एकेडमी के मुख्य कोच और संस्थापक नीतीश शर्मा और सुनहरा वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष अरुणेश्वर सुनहरा ने बताया कि इसका मुख्य मकसद महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार करना और विकट परिस्थितियों में अपनी आत्म रक्षा करने के योग्य बनाना है ! ये रेगुलर मिश्रित करके इस तकनीक को बनाया गया है !! ये बहुत ही घातक और अपने में सर्वश्रेष्ठ आत्म रक्षा प्रशिक्षण है ! जिसका उपयोग इंडियन आर्मी और इजराइल आर्मी अपनी आत्म रक्षा के लिए करती है।

जन संपर्क हेतू संपर्क करें।
डॉ. वर्षा चौधरी
+91 75668 30993

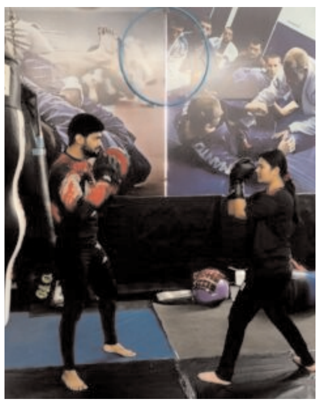

झण्डा दिवस के अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों को लगाया गया फ्लैग

शहडोल। सशस्त्र झण्डा दिवस के अवसर पर आज जिला सैनिक कल्याण अधिकारी श्री धीरेन्द्र सिंह द्वारा कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य, अपर कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री हिमांशु चंद्र, जिला कोषालय अधिकारी श्री आरएम सिंह सहित अन्य अधिकारियों को फ्लैग लगाया गया। साथ ही सशस्त्र सेना दिवस के झंडे लगाकर दान की राशि एकत्रित की गई। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने जानकारी दी है कि शासन द्वारा इस वर्ष शहडोल जिले में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर 4.26 लाख रुपए की धनराशि एकत्रित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर ध्वज बेचकर जो धनराशि एकत्रित की जाती है उसे मृत सैनिकों के परिवार, सेवा के दौरान विकलांग हुए सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के परिजनों के सहायतार्थ उनके पुनर्वास हेतु खर्च की जाती है साथ ही सशस्त्र सेना झंडा दिवस में दान की गई राशि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 297 (2)के अंतर्गत आयकर से मुक्त होती है। गौरतलब है कि 7 दिसम्बर 1949 से देश में सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि शहीदों और वर्दी में उन लोगों को सम्मानित किया जा सके जिन्होंने देश के सम्मान की रक्षा हेतु देश की सीमाओं पर बहादुरी से दुश्मनों का मुकाबला किया और अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है।

छात्र अर्जुन अहिरवार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया

रायसेन। शहर के खेल स्टेडियम में शनिवार को विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर कई प्रतियोगीताएँ रखी गई। जिसमे दौड़ प्रतियोगीता मे एकीकृत शा. मा. शाला बनखेडी वि. ख. उदयपुरा के छात्र अर्जुन अहिरवार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। शाला प्राचार्य व शिक्षकों ने भी बधाई दी। इस अबसर पर स्वास्थ मंत्री डॉ

प्रभु राम चौधरी एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव जी भी कार्यक्रम मे शामिल हुए। अर्जुन अहिरवार को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। माता पिता ने बच्चे के भविष्य के प्रति जागरूक एवं खेल में कैरियर बनाने में सहयोग करते रहेंगे भारत देश के लिए अर्जुन मेडल लेकर आए बस यही सपना हैं ।

शासकीय और निजी विश्वविद्यालय सामुदायिक सेवा के लिए हर वर्ष 5-5 गाँव गोद लें : राज्यपाल श्री पटेल

भोपाल। श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि सभी निजी और शासकीय विश्वविद्यालय अधिक से अधिक रोजगारमूलक पाठ्यक्रम संचालित करें। पाठ्यक्रमों की उच्च गुणवत्ता के मानकों का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह में निजी कंपनी और उद्योगों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए। कुलपति का नाम कुलगुरू किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यपाल श्री पटेल राजभवन के सांदीपनि सभागार में समन्वय समिति की 100 वीं बैठक को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि शासकीय और निजी विश्वविद्यालय हर वर्ष 5-5 गाँव गोद लेकर स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामुदायिक सेवा के कार्यों का संचालन करें। राष्ट्रीय सेवा योजना और सामुदायिक सेवा के कार्यों के समान ही रेडक्रॉस सोसायटी के साथ समन्वय कर, मानवता की सेवा के कार्यों में योगदान दें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा युवाओं को जमीन से जुड़े रहते हुए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम बनने का अवसर दिया है। नीति के प्रभावी और एकीकृत क्रियान्वयन के लिए विश्वविद्यालय अधिनियमों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप संशोधन का कार्य समय-सीमा में पूरा किया जाए। निजी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, कुलपति और गवर्निंग कॉउन्सिल में अधिकारियों के समय-सीमा में नामांकन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आवश्यक होने पर प्रक्रिया और नियमों में संशोधन किया जाए। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों का देश-दुनिया में नाम हो। सभी विश्वविद्यालयों की उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्र के रूप में पहचान बने। इसके लिए एकजुट और एकरूपता के साथ प्रयास किये जायें। निर्धारित कैलेंडर के अनुसार प्रवेश, परीक्षा और परिणाम घोषित हों। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विश्वविद्यालय काम के आधार पर पहचान बनायें। विश्वविद्यालय क्षेत्रीय संसाधन और संभावनाओं से सम्बद्ध जैसे वनांचल में वन, दर्शनीय क्षेत्रों में पर्यटन संबंधी और औद्योगिक क्षेत्र में उद्योगों के अनुरूप पाठ्यक्रम संचालित करें।

जन आवाज मंच, मैहर में सभा सम्पान

सतना। 4 दिसंबर दिन रविवार को पेंशन महाकुंभ मैहर जिला सतना में पेंसन महाकुंभ में जन आवाज मंच की और से शामिल हुए । साथ मे कोर टीम के साथी व रोजगार सहायक संघ के प्रदेश संयोजक साथी राजनारायण सिंह जी व पी एच ई हैंडपंप टेक्नीशियन संघ के महामंत्री साथी हरिदास जी अध्यापक संघ से प्यारेलाल लड़िया जी अजाक्स संघ के वरिष्ट साथी शंकर लाल कोरी जी आजीविका मिशन के साथी स्पतेन्द्र मिश्रा सहित अन्य साथी शामिल हुए सभी से विचार विमर्श हुआ ताकि सभी की उचित मांगो को हल करवाने हेतु संघर्ष तेज किया जा सके। एकजुट हो संघर्ष को तेज करने का वक्त आ गया है शासन-प्रशासन अपनी मिलीभगत के तहत हमारे जन मुहिम को कमजोर करना चाहती है। आखिर हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे बेरोजगारी चरम सीमा पर आ चुकी है महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। आम आदमी किस तरह से अपने जीवन व्यतीत कर रहा है इस पीड़ा को शासन प्रशासन के लोग समझते नहीं है और समझना भी नहीं चाहते हैं हम अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं।

वन मंत्री डॉ शाह ने रातापानी अभ्यारण में जंगल सफारी का किया शुभारंभ
मलखार गांव में नवनिर्मित ग्रामीण शिल्प कला केंद्र का भी किया उद्घाटन

❑रायसेन

वन मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह तथा भोजपुर विधायक सुरेन्द्र पटवा द्वारा रायसेन जिले में रातापानी अभ्यारण में जंगल सफारी का शुभारंभ किया गया। उन्होंने प्रातः 07 बजे रातापानी अभ्यारण के झिरी गेट पर अनुभूति कार्यक्रम के तहत हरी झण्डी दिखाकर स्कूली बच्चों को सफारी वाहन से जंगल सफारी पर रवाना किया गया।

वन मंत्री डॉ शाह तथा विधायक पटवा द्वारा भी जंगल सफारी की गई। इसके अतिरिक्त वन मंत्री एवं विधायक पटवा द्वारा मलखार गांव में नवनिर्मित ग्रामीण शिल्प कला केंद्र का उद्घाटन भी किया गया एवं उपस्थित ग्रामीणों से चर्चा की गई। झिरी गेट की सफारी 40 किमी की है जिसमें जंगल एवं वन्यप्राणियों के अलावा केरी महादेव, रणभैंसा, मलखार विलेज क्राफ्ट सेंटर आकर्षण के मुख्य केंद्र है। इस

गेट पर 6 सफारी वाहन अनुबंधित किए गए है। पर्यटक 3000 रुपए सफारी शुल्क, 480 रुपए गाइड शुल्क एवं 750 रुपए प्रवेश शुल्क दे कर इस सफारी का लुफ्त उठा सकते है। देलवाड़ी गेट की सफ़ारी 20 किमी की है। इस मार्ग पर पर्यटक प्रकृति के अनुपम छटा से भरी घाटियों, युद्धबंदी शिविर, सनसेट पॉइंट एवं गिन्नौरगढ़ किले के पैदल भ्रमण का लुफ्त उठा सकते है। इस गेट पर 3 सफारी वाहन अनुबंधित किये गए है। पर्यटक 2600 रुपए सफारी शुल्क, 480 रुपए गाइड शुल्क एवं 750 रुपए प्रवेश शुल्क दे कर इस सफारी का लुफ्त उठा सकते है। रातापानी अभ्यारण्य इस प्रकार की जंगल सफारी प्रारंभ करने वाला पहला वन्यप्राणी अभ्यारण्य है। इस प्रयास से स्थानीय लोगों को गाइड, फूड स्टॉल, सफारी वाहन इत्यादि में रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे एवं लोगों में वन और वन्य प्राणियों के प्रति जागरूकता भी विकसित होगी।

प्रदेश में 226 नई स्वास्थ्य संस्थाएँ शुरू करने की मंत्रि-परिषद ने दी मंजूरी

❑रायसेन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि मंगलवार को मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में 226 नई स्वास्थ्य संस्थाएँ शुरू करने को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रदेश

की जनता के लिये बहुत बड़ी सौगात है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का नई स्वास्थ्य संस्थाओं को स्वीकृति देने पर आभार व्यक्त किया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि प्रदेश में शुरू की जाने वाली नई 226 स्वास्थ्य संस्थाओं में 191 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 21 सिविल अस्पताल, 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और 2 उप स्वास्थ्य केन्द्र शामिल हैं। इन संस्थाओं को शुरू करने के लिये 1093 करोड़ 67 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है। रायसेन जिले को मिले 4 पीएचसी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि रायसेन जिले के लिये 4 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शुरू करने की मंत्रि-परिषद द्वारा मंजूरी दी गई है। रायसेन जिले के लिये स्वीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में बरेली विकासखण्ड में अमरावद, औबेदुल्लागंज विकासखण्ड में उमरावगंज और विनेका, गैरतगंज विकासखण्ड में हरदोट और रजपुरा, बेगमगंज विकासखण्ड में सुनवाहा और मरखेड़ा टप्पा शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने कहा कि प्रदेश की जनता को बेहतर उपचार की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिये और विशेषकर ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में, जहाँ अभी स्वास्थ्य सेवाओं का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, वहाँ इन संस्थाओं को शुरू किया जा रहा है।

होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस मनाया गया

__सीहोर।__ 76 वां होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस कार्यालय ड्रिस्टिक्ट कमाण्डेंट होमगार्ड के परेड ग्राउण्ड पर हर्षोल्लास से मनाया गया। स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर परेड निकाली गई। परेड का आयोजन प्लाटून कमाण्डर अशोक पाटीदार के नेतृत्व में किया गया। परेड में चार प्लाटून शामिल किये गये। जिसमें दो प्लाटून होमगार्ड तथा एक-एक प्लाटूनएसडीआरएफ एवं ऑक्सफोर्ड हायर सेकण्डरी स्कूल का बैण्ड ग्रुप शामिल हुआ। परेड के आयोजन अवसर पर परेड कमाण्डरद्वारा मुख्य अतिथियों को परेड की सलामी दी गई। कार्यक्रम के जिला पंचायत अध्यक्षगोपाल इंजीनियरएवं नगरपालिका अध्यक्ष प्रिंसराठौर द्वारा परेड का निरीक्षण किया गया। होमगार्ड स्थापनादिवस समारोह में सेवानिवृत्त होमगार्ड अधिकारी, कर्मचारी एवं होमगार्ड जवानपत्रकार उपस्थित थे।

आदिवासी छात्रा को चोरी के शक में हॉस्टल में जूतों की माला पहनाकर घुमाया, अधीक्षिका निलंबित

❑ बैतूल

बैतूल जिले में आदिवासी बालिका छात्रावास में पैसे चुराने के संदेह में एक छात्रा को जूतों की माला पहनाकर घुमाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार छात्रावास के अधीक्षक ने पांचवीं कक्षा की एक छात्रा को कथित तौर पर जूतों की माला पहनाकर घुमाया, मामला सामने आने के बाद बैतूल जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिये हैं। घटना पिछले सप्ताह दमजीपुरा गांव के एक सरकारी आदिवासी बालिका छात्रावास की बताई जा रही है।

इसकी शिकायत करने के लिए लड़की के परिजन मंगलवार को जिलाधिकारी अमनवीर सिंह बैंस के कार्यालय पहुंचे। लड़की के पिता की शिकायत सुनने के बाद बैंस ने कहा कि उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। आदिवासी मामलों के विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि छात्रावास की महिला अधीक्षक को पद से हटा दिया गया है। लड़की के पिता ने मीडिया को बताया कि जब वह अपनी बेटी से दमजीपुरा में आदिवासी छात्रावास में मिलने गए तो उनकी बेटी ने उन्हें इस बात की जानकारी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी पर भूत जैसा दिखने के लिए मेकअप किया गया था और अधीक्षक द्वारा दूसरी लड़की के 400 रुपये चोरी करने के आरोप में उसे जूतों की माला पहनाकर छात्रावास परिसर में घुमाया गया।

स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा रोचक अंदाज में होगी पढ़ाई

अब आंगनबाड़ी से ही मनोरंजक अंदाज में पढ़ाएंगे शिक्षक दूसरी तक बस्ता, तो पांचवीं तक किताबें भी अनिवार्य नहीं

❑ इंदौर

नए सत्र से प्रदेश के स्कूलों का माहौल बदला-बदला होगा। छोटे बच्चों को किताबों और बस्तों के बोझ से मुक्ति दिलाते हुए रोचक अंदाज में शिक्षा दी जाएगी। यही नहीं आंगनबाड़ी से ही अक्षरज्ञान पर जोर दिया जाएगा। वर्तमान में कम शिक्षित कार्यकर्ता ही बच्चों से रूबरू होती हैं।

अब इनमें अधिक पढ़े-लिखे शिक्षकों की भर्ती की जाएगी जो पहले तीन साल बच्चों की शिक्षा का आधार मजबूत करेंगे। इतना ही नहीं पहली-दूसरी कक्षा भी बस्ताविहीन रहेंगी। प्राथमिक कक्षाओं की किताबें शिक्षकों के लिए छपेंगी, जो विद्यार्थियों को किस्से-कहानियों से शिक्षित करेंगे। तीसरी से पांचवीं तक भी किताबें अनिवार्य नहीं रहेंगी। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने प्रदेश की नई शिक्षा नीति साझा करते हुए बताया, सबसे बड़ी बात पांचवीं तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी। शिक्षक रोचक उदाहरणों के माध्यम से सामान्य गणित एवं सामान्य ज्ञान की शिक्षा देंगे। कुल मिलाकर विद्यार्थी के सिर से पढ़ाई का बोझ कम कर उन्हें नॉलेज देने पर फोकस रहेगा। ताकि वे रट्टा मार मानसिकता से बाहर आकर अपने कौशल के अनुसार करियर बना सकें। उन्होंने कहा, अब पांचवीं और आठवीं में परीक्षा ली जाएगी। आठवीं तक सीधे

अगली कक्षा में प्रमोशन देने से सबसे अधिक दिक्कत 10वीं बोर्ड में आती है इसलिए पांचवीं से ही छलनी लगाई जाएगी। पंवार ने कहा, हालांकि ये परीक्षाएं बोर्ड पैटर्न पर न होकर कक्षा स्तर के ज्ञान को परखने के लिए लघु उत्तरीय सवालों के जरिये ली जाएगी ताकि विद्यार्थी को परीक्षा का महत्व समझ आए। परमार ने बताया, केंद्र सरकार की शिक्षा नीति 5+3+3+4 पैटर्न को लागू किया जाएगा। नए पैटर्न में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के तहत पहले 5 साल में तीन वर्ष आंगनबाड़ी और 2 वर्ष पहली-दूसरी कक्षा के रहेंगे। अगले तीन साल तीसरी से पांचवीं तक प्रयोग आधारित शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद 3 साल मिडिल और 4 साल हायर सेकंडरी होगी। पहले 5 साल की किताबें तैयार हैं। जल्द घोषणा होगी। फिर चार साल में 12वीं तक पूरा नया पैटर्न लागू हो जाएगा। कोर्स में केंद्र के सिलेबस के साथ स्थानीय सामग्री भी जोड़ी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने बताया, अब छठवीं कक्षा से व्यावसायिक प्रशिक्षण इंटर्नशिप भी शुरू की जाएगी। इससे विद्यार्थी को ग्रेडिंग सुधारने और अपने हुनर को निखारने में कम उम्र से ही काफी मदद मिलेगी। अब छठवीं से ही कम्प्यूटर और मोबाइल एप्लीकेशन की शिक्षा दी जाएगी और कोडिंग सिखाई जाएगी। इसके लिए स्कूलों में डिजिटल इंतजाम किए जाएंगे। स्कूलों में वर्चुअल लैब डेवलप की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल किया जाएगा। विषयवार कंटेंट को विद्यार्थी ज्यादा आसानी से समझ या सीख सकें इसलिए कंटेंट क्षेत्रीय भाषा में भी अनुवादित किए जाएंगे।

कक्षा नौवीं से बारहवीं तक अब तीनों भाषाएं हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत अनिवार्य की जाएंगी। अभी तक ऐच्छिक होने के कारण संस्कृत को हटा दिया जाता रहा है। व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी। मार्कशीट में नंबरों की जगह ग्रेड दी जाएगी। इससे विद्यार्थी का समग्र मूल्यांकन हो सकेगा। नौवीं कक्षा से सब्जेक्ट चुनने की आजादी रहेगी। यानी पहले की तरह आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कृषि, गणित विषय चुनने जैसी बाध्यता नहीं रहेगी। विद्यार्थी इन सबके कॉम्बिनेशन वाले कोई भी तीन विषय ले सकेंगे।

शिप्रा नदी के साफ पानी में अब लगा सकेंगे भक्त डुबकी, 600 करोड़ में होगी साफ

❑ इंदौर

उज्जैन की शिप्रा नदी में अब कान्ह नदी का दूषित पानी नहीं मिलेगा। भक्त साफ पानी में डुबकी लगा सकेंगे और आचमन भी कर पाएंगे। कान्हा नदी डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना को कैबिनेट बैठक में स्वीकृति दी गई। छह साल बाद लगने वाले सिंहस्थ के लिए यह सारी कवायद सरकार अभी से शुरू करने जा रही है। सिंहस्थ में लाखों भक्त स्नान के लिए आते है। पिछले सिंहस्थ में सरकार ने शिप्रा नदी में नर्मदा नदी का पानी प्रभावित किया था। इन्दौर के समीप बहने वाली कान्ह नदी के दूषित जल को शिप्रा नदी में मिलने से रोकने के लिए जल संसाधन विभाग की 598 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है। कान्ह नदी में इन्दौर शहर एवं औद्योगिक क्षेत्र का प्रदूषित जल मिलता है। कान्ह नदी आगे चल कर उज्जैन के समीप क्षिप्रा में मिलती है। शिप्रा नदी के जल को कान्ह नदी के दूषित जल से बचाने के लिये कान्ह नदी डायवर्शन क्लोज डक्ट परियोजना तैयार की गई है। इस प्रोजेक्ट को वर्ष 2028 के महाकुंभ सिंहस्थ के मद्देनजर अभी मंजूरी दी गई है, ताकि तब तक काम पूरा हो सके।

संपादकीय

विपक्ष के तेवर देखकर लगता है संसद के शीतकालीन सत्र में मुद्दों की गर्माहट बनी रहेगी

संसद के शीतकालीन सत्र में राजनीतिक मुद्दों की गर्माहट बने रहने के आसार हैं क्योंकि सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने जिस तरह सरकार के समक्ष मुद्दों की भरमार की है उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि यह सत्र हंगामेदार रहेगा। इसके अलावा इस सत्र की शुरुआत ऐसे समय हो रही है जब दिल्ली नगर निगम चुनाव, गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव, एक लोकसभा सीट और छह विधानसभा सीटों के उपचुनाव परिणाम आने हैं। जाहिर है यदि भाजपा सर्वाधिक चुनावों में विजयी होती है तो सत्र के दौरान सरकार का मनोबल बढ़ा रहेगा और यदि इन चुनावों में जीत विपक्ष के हाथ लगती है तो सत्र के दौरान वह सरकार पर हावी होने का प्रयास कर सकता है। संसद का यह सत्र वैसे तो नये संसद भवन में होना था लेकिन वहां निर्माण कार्य अभी चलते रहने की वजह से इसे पुराने संसद भवन में ही आयोजित किया गया है। इस सत्र की खास बात यह होगी कि राज्यसभा सभापति के नाते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहली बार सदन का संचालन करेंगे। गौरतलब है कि मॉनसून सत्र के समापन के समय तत्कालीन उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू राज्यसभा सभापति के नाते सदन का संचालन कर रहे थे। संसद का शीतकालीन सत्र सात दिसंबर से शुरू हो रहा है और यह 29 दिसंबर को समाप्त होगा। इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। हम आपको यह भी बता दें कि सरकार ने पिछले सप्ताह शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किये जाने वाले 16 विधेयकों की सूची जारी की थी। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए विपक्ष ने जहां सरकारी एजेंसियों के कथित दुरुपयोग, महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दे अपनी सूची में रखे हैं तो वहीं सरकार के पास भी विधायी कार्यों की लंबी सूची है। सरकार की ओर से बुलाई गयी सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने साफ कर दिया है कि उसकी प्राथमिकता में महंगाई, बेरोजगारी, चीन से लगी सीमा की स्थिति, कॉलेजियम के मुद्दे से जुड़ा विषय, कश्मीर से हिंदुओं का पलायन, किसानों को फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, केंद्र राज्य संबंध एवं संघीय ढांचे का विषय और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण पर अदालती फैसले आदि रहेंगे।

सीमा विवाद को राज्यों के भरोसे छोड़ना सही नहीं होगा

देश में करीब दस राज्य ऐसे हैं, जिनमें सीमा को लेकर विवाद जारी है। इनमें पूर्वोत्तर राज्यों में सर्वाधिक फसाद है। राज्यों के विवादों को उकसाने से स्थानीय लोग हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जिन क्षेत्रों की दावेदारी को लेकर विवाद या हिंसक कार्रवाई हो रही है, उनका कोई विशेष वाणिज्यिक या दूसरा महत्वपूर्ण उपयोग नहीं है, जिससे राज्यों को किसी तरह का भारी नुकसान हो रहा हो। इसके बावजूद राज्यों की सरकारें क्षेत्रवाद के नाम पर उकसावे भरी कार्रवाई से लोगों को हिंसा की तरफ धकेल रही हैं। मेघालय से पहले अक्टूबर के पहले सप्ताह में असम का मिजोरम से विवाद हो गया था। इस विवाद की जड़ झोपड़ी रही।

असम-मेघालय सीमा पर बीते दिनों हिंसा भड़कने से कई लोगों की मौत हुई और कई घायल हो गए। घटना में मेघालय के पांच और असम के एक वन रक्षक सहित कुल छह लोगों की मौत हो गई। हालांकि यह हिंसा लकड़ी की तस्करी को लेकर हुई लेकिन इन राज्यों में सीमा विवाद को लेकर भी हिंसा होना आम बात है। पूर्वोत्तर सहित देश के कई राज्यों में सीमा विवाद चल रहा है, किन्तु भौगोलिक सीमा और क्षेत्रों की दावेदारी को लेकर जितना खूनी संघर्ष पूर्वोत्तर के राज्यों में हुआ है, उतना कहीं नहीं हुआ। राज्य विवादित क्षेत्र के निपटारे के लिए कानूनी या लोकतांत्रिक तरीका अपनाने की बजाए दुश्मनों की तरह जंग छेड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में जब देश चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों की चुनौतियों से जूझ रहा है, राज्यों द्वारा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बजाए निहित स्वार्थों के वशीभूत होकर की गई कार्रवाई से एकता और अखंडता को लेकर गलत संदेश जा रहा है। विशेषकर चीन पहले ही अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जता कर विवाद खड़ा कर चुका है।

देश में करीब दस राज्य ऐसे हैं, जिनमें सीमा को लेकर विवाद जारी है। इनमें पूर्वोत्तर राज्यों में सर्वाधिक फसाद है। राज्यों के विवादों को उकसाने से स्थानीय लोग हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जिन क्षेत्रों की दावेदारी को लेकर विवाद या हिंसक कार्रवाई हो रही है, उनका कोई विशेष वाणिज्यिक या दूसरा महत्वपूर्ण उपयोग नहीं है, जिससे राज्यों को किसी तरह का भारी नुकसान हो रहा हो। इसके बावजूद राज्यों की सरकारें क्षेत्रवाद के नाम पर उकसावे भरी कार्रवाई से लोगों को हिंसा की तरफ धकेल रही हैं। मेघालय से पहले अक्टूबर के पहले सप्ताह में असम का मिजोरम से विवाद हो गया था। इस विवाद की जड़ झोपड़ी रही। असम पुलिस ने दो अक्टूबर को झोफई इलाके में दो झोपड़ियां बनाईं। जिस स्थान पर झोपड़ियां बनाई गईं वह मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री सी छुंगा के धान के खेत के बिल्कुल सामने मौजूद थी। हालांकि, असम पुलिस ने झोपड़ियां हटा

लीं। दरअसल, जिसे इलाके में असम पुलिस ने झोपड़ियां बनाई वह विवादित क्षेत्र है। इस विवादित क्षेत्र पर दोनों राज्य सरकारों ने अच्छी स्थिति बनाए रखने पर सहमति जताई थी। गौरतलब है कि मार्च 2018 में इसी इलाके में झड़प हुई थी जब मिजोरम पुलिस के पदाधिकारियों ने वहां लकड़ी का एक मकान बनाने की कोशिश की थी। उस झड़प में 60 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस साल सितंबर में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सीमा मुद्दे को लेकर मुलाकात भी की थी और मंत्री स्तरीय बात जारी रखने पर सहमति जताई थी। सीमा विवाद को लेकर असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों की कई दौर की बैठकों के बावजूद कोई हल नहीं निकल पाया। सीमा विवाद को लेकर पूर्वोत्तर राज्यों का इतिहास रक्तरंजित रहा है। साल 2021 में एक दंपत्ति कछार (असल) जिले के रास्ते मिजोरम आ रहे थे। जिस समय वह लौट रहे थे तो उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई। बवाल इतना बढ़ गया कि नौबत फायरिंग तक जा पहुंची। इससे पहले साल 2020 में अक्टूबर में भी दो बार असम और मिजोरम की सीमा पर आगजनी और हिंसा हुई थी। 9 अक्टूबर, 2020 को मिजोरम के दो लोगों को आग लगा दी गई थी। इसी के साथ कई झोपड़ियों और सुपारी के पौधों को भी आग के हवाले कर दिया गया था। वहीं कुछ दिन बाद ही कछार (असम) के लोगों ने मिजोराम पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस और आम लोगों पर पत्थरबाजी हुई।

असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद ब्रिटिश राज के समय से करीब 100 साल से चल रहा है। असम और मिजोरम के बीच 164.6 किलोमीटर की अंतर-राज्य सीमा है, जिसमें असम के तीन जिले कछार, हैलाकांडी और करीमगंज, मिजोरम के कोलासिब, ममित और आइजोल जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। ब्रिटिश राज के समय से मिजोरम को असम के लुशाई हिल्स के रूप में जाना जाता था। मिजोरम विद्रोह के वर्षों के बाद 1987 में ही एक राज्य बन गया था, लेकिन अभी भी राज्य ब्रिटिश काल में 1875 में तय की गई सीमा को अपना मानता है। इन दोनों राज्यों के अलावा असम-मिजोरम, हरियाणा-हिमाचल प्रदेश, लद्दाख-हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र-कर्नाटक, असम-अरुणाचल प्रदेश और असम-नागालैंड के बीच सीमा विवाद है। यहां सीमाओं के सीमांकन और क्षेत्रों के दावों के बीच विवाद है। इनमें महाराष्ट्र और कर्नाटक में सीमा के दावों को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। दोनों राज्यों की सरकारें सिर्फ क्षेत्रीय लोगों की भावनाओं को उकसाने में जुटी हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने महाराष्ट्र के 40 गांवों पर अपना दावा किया है। इसका जवाब देते हुए महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र का कोई भी गांव कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी सीमा विवादों का निपटारा राज्यों के स्तर पर करना आसान नहीं हैं। किन्तु ऐसे संवेदनशील मुद्दे को उछाल कर राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करना राजनीतिक दलों का एजेंडा रहा है। राज्यों में विवाद चाहे सीमा संबंधी हों, नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर या किसी दूसरी तरह का हो, इनका निराकरण सर्वमान्य कानूनी तरीके से ही किया जाना चाहिए।

आरओबी का लोकार्पण, हाइवे और करोड़ों की सौगात देंगे सीएम

छिंदवाड़ा। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नौ दिसंबर को बिछुआ में आयोजित कार्यक्रम में जिले को कई सौगातें देंगे। वे छिंदवाड़ा शहर में बने रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे। छिंदी से जुन्नारदेव व बंडोल से चौरई तक स्टेट हाइवे के भूमिपूजन सहित जिले में पीडब्ल्यूडी, एमपीआरआरडी, जल संसाधन सहित अन्य विभागों के करोड़ों रुपये के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण करेंगे। प्रशासन सभी विभागों के निर्माण कार्यों की सूची और लोकार्पण - भूमिपूजन के शिलालेख की तैयारी में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब सौ करोड़ रुपये की लागत के तीस निर्माण कार्यों का भूमिपूजन व लोकार्पण मुख्यमंत्री करेंगे। लोक निर्माण विभाग की एक दर्जन सड़कों का भूमिपूजन भी प्रस्तावित है। जल संसाधन विभाग के ग्यारह स्टॉप डैम और जलाशयों का भूमिपूजन और आठ जलाशयों का लोकार्पण भी बिछुआ में होगा। इसके अलावा अन्य विभागों के निर्माण कार्यों की भी सौगातें मिलने वाली है। लोकार्पण को लेकर सबसे ज्यादा राजनीति छिंदवाड़ा नगर निगम के आरओबी को लेकर हो रही है। कांग्रेस ने तो ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आयोजन में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को प्रोटोकाल के साथ आमंत्रित करने की मांग रखी है।

प्रकृति की चेतावनी को बार-बार नजर अंदाज करना बहुत भारी पड़ सकता है

यदि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के वरिष्ठ वैज्ञानिकों की मानें तो बढ़ते तापमान का असर आने वाले दिनों में तेजी से देखा जाएगा। संभावना तो यहां तक व्यक्त की जा रही है कि यही हालात रहे तो जीवन-दायिनी गंगा-जमुना नदी में जल स्तर कम होगा और हालात यहां तक हो सकते हैं कि गंगा-जमुना के बहाव क्षेत्र में तेजी से पानी का स्तर कम होगा। यहां तक कि इस क्षेत्र में पानी का संकट तक आ सकता है। यह चेतावनी आज की नहीं है अपितु भूविज्ञानियों व पर्यावरणविदों द्वारा लंबे समय से दी जाती रही है। प्रकृति लगातार डेढ़-दो दशक से चेताती जा रही है पर अनदेखा किया जा रहा है। हालिया दशकों में हिमालय पर्वत माला श्रृंखला में सर्वाधिक भूगर्भीय हलचल देखने को मिल रही है। साल में एक दो नहीं अपितु आये दिन धरती हिलने लगी है। भूस्खलन होने लगे हैं। साल में एक दो बार तो बड़े भूस्खलन आम होते जा रहे हैं। देवभूमि आज भूगर्भीय हलचल का केन्द्र बन गई है। हिमालय श्रृंखला के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। यहां तक कि हिमालयी श्रृंखला से निकलने वाली नदियों के उद्गम स्थल लगातार पीछे खिसकते जा रहे हैं। पिछले सालों में विनाश के भयावह हालातों से हम रूबरू हो चुके हैं।

दरअसल गंगा-जमुना के उद्गम स्थल या यों कहें कि संपूर्ण उत्तराखंड क्षेत्र जिसमें चार धाम आते हैं, सनातन काल से आस्था का केन्द्र रहे हैं। इनकी अपनी अहमियत रही है तो प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में भी हिमालय क्षेत्र की अपनी भूमिका रही है। समय का बदलाव देखिये कि यहां तक तो सब ठीक है कि इस क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है। आज चारधाम की यात्रा सहज और आम आदमी की पहुंच में आई है। मुझे और मेरी जैसी पुरानी पीढ़ी के लोगों को अच्छी तरह से याद है कि चार धाम की यात्रा पर जाने से पहले और यात्रा से सकुशल वापसी पर वृहद आयोजन होते थे। हमने तो यहां तक देखा है कि गंगाजी की यात्रा करने पर चाहे वह हरिद्वार की हो या ऋषिकेश की, गंगाजल के पूजन का भव्य आयोजन होता था जिसे गंगोज के नाम से जाना जाता था। घर-परिवार और नाते-रिश्तेदार जुटते थे, पूजन-हवन होता था और फिर सहभोज तो होना ही था। आज परिस्थितियों में बदलाव आया है। गंगा-जमुना का यह पवित्र क्षेत्र आज आस्था से अधिक पर्यटन का केन्द्र बन गया है। लोग घूमने के बहाने जाते हैं। यहां तक तो ठीक कहा जा सकता है पर जिस तरह से प्रतिबंधित वस्तुओं खासतौर से प्लास्टिक और इसी तरह की सामग्री का कचरा केन्द्र बहाने से पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या आम हो गई है। लोग चंद घंटों के लिए जाते हैं और प्लास्टिक कचरा और अन्य सामग्री वहां छोड़ आते हैं। इसी तरह से विकास के नाम पर जिस तरह से कंक्रीट का जंगल विकसित किया जा रहा है उसे भी पर्यावरण की दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता है। हजारों की संख्या में प्रतिदिन वाहनों की रेलमपेल से प्रदूषण फैल रहा है वो अलग। इससे क्षेत्र के वातावरण में बदलाव आ रहा है। तापमान बढ़ने लगा है।

डॉ. जयशंकर ने भारत की विदेश नीति को ऊर्जावान और गतिशील बनाया

19-20 नवंबर, 2022 को भारत में तीसरे दो दिवसीय नो मनी फॉर टेरर के मंत्रिपरिषदीय सम्मलेन हुआ जिसमें 75 देशों के 450 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। गृहमंत्री अमित शाह ने अपने भाषण में कहा कि भारत नो मनी फॉर टेरर संस्था का स्थायी सचिवालय स्थापित करने के लिए भी तैयार है। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने भी आतंकवाद से निपटने के लिए अविभेदित और अविभाजित दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देते हुए राष्ट्रों से राजनीतिक विभाजन से ऊपर उठने का आग्रह किया। उन्होंने कुछ देशों द्वारा आतंकवाद को राज्य-शिल्प (स्टेट क्राफ्ट) के रूप में पोषित करने का आरोप भी लगाया। ऐसे में भारत ने दुनिया के सामने आतंकवाद निरोधी लड़ाई में विश्व का अगुआ बनने की दिशा में एक और निर्णायक कदम बढ़ा लिया है। भारत की ऊर्जावान एवं मुखर विदेश नीति ने सबका ध्यान आकर्षित किया है। आइये विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर के विचारों के आलोक में भारत की बदलती विदेश नीति का अवलोकन करते हैं। अपने 75 वर्षों का सिंहावलोकन करें तो हम यह पाते हैं कि

यह पूरी यात्रा इतनी आसान भी नहीं रही है। एक लंबी इस्लामी-ब्रिटिश परतंत्रता के बाद जब देश आजाद हुआ तो पूरी दुनिया ने इसके विफल होने की भविष्यवाणियां की थी। भारत ने अपने जिजीविषा एवं संघर्ष के बल पर आज एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थाई सदस्य ना होते हुए भी आज दुनिया के सभी स्थाई एवं अस्थाई सदस्य भारत के विचारों अथवा पक्ष को जानने के लिए लालायित रहते हैं। वैश्विक स्तर पर यदि हम अपने 75 वर्षों की विदेश नीति पर विचार करें तो पाते हैं कि दुनिया के अन्य देशों के द्वारा खड़ी की गयीं समस्याएं वास्तव में भारत के लिए मुख्य बाधाएं नहीं थीं अपितु भारत के द्वारा स्वयं से बनाई गईं।

शिकायतों के निराकरण के लिए शिकायतकर्ताओं से संवाद करें अधिकारी : कलेक्टर

❑सीहोर

शिकायतों के संतुष्टिपूर्ण एवं शीघ्र निराकरण के लिए शिकायतकर्ताओं से संवाद करना आवश्यक है। संबंधित विभाग के जिला अधिकारी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थ संबंधित अधिकारी-कर्मचारी हितग्राहियों, शिकायतकर्ताओं से मिलकर चर्चा करेंगे तो शिकायतों का निराकरण तेजी से होगा। यह बात कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित टीएल मीटिंग में कही। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन, समाधान ऑनलाइन, जनसुनवाई तथा मुख्यमंत्री के भ्रमण के दौरान प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की विस्तार से समीक्षा करते हुए सभी आवेदनों का समय सीमा में निराकरण करने के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए।

कलेक्टर सिंह ने शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकानों से राशन वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी पात्र हितग्राहियों को शत-प्रतिशत राशन वितरित किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्नोत्सव के दिन 35 प्रतिशत राशन वितरण किया जाए। धान उपार्जन केन्द्रों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर सिंह ने कहा कि धान उपार्जन केन्द्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। ताकि धान विक्रय

के लिए आने वाले किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि जिले में खाद की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।जल जीवन मिशन के कार्यो की समीक्षा करते हुए कलेक्टर सिंह ने जल जीवन मिशन में कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के अधिकारी निर्माणाधीन शासकीय भवन का निरीक्षण करें और कमी पाए जाने पर तुरंत सुधार करें। उन्होंने टीएल बैठक मे अनुपस्थित रहने वाले तथा सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को शोकाज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ हर्ष सिंह ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती गुंचा सनोबर, संयुक्त कलेक्टर बृजेश सक्सेना, सतीश राय, सुवंदना राजपूत, एसडीएम अमन मिश्रा सहित अनेक विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

राजस्व प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर सिंह ने सभी राजस्व अधिकारियों को राजस्व संबंधी प्रकरणों को निराकरण समय सीमा में पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नामांतरण, बँटवारा, सीमांकन, डायवर्सन, राजस्व वसूली सहित अन्य राजस्व प्रकरणों के साथ ही राजस्व न्यायालयों के लम्बित प्रकरणों की नियमित समीक्षा करें और समय सीमा में उनका निराकरण करें। कलेक्टर सिंह ने मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान छूटे हुए मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ने के लिए सभी एसडीएम, तहसीलदार की सराहना की है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए सभी बीएलओं को स्कूल-कॉलेजों में भेजने के निर्देश दिए।

विधायक से शिकायत की तो सरपंच ने ग्रामीणों के घर पानी की सप्लाई बंद की

❑ दमोह

दमोह जिले के पथरिया विधानसभा में आने वाला घोघराकला गांव। ये गांव तब चर्चा में आया था जब सरपंच के भ्रष्टाचार को साबित करने के लिए ग्रामीणों ने विधायक के सामने गंगाजल उठाया था। ग्रामीणों ने कसम खाकर कहा था कि सरपंच खुमान सिंह ने पीएम आवास योजना के लिए हमसे रिश्वत ली थी। ग्रामीणों की शिकायत के बाद विधायक ने उनके पैसे वापस करवाए थे। जिसके बाद सरपंच ने पूरे गांव की पानी की सप्लाई बंद करा दी।

विधायक ने सरपंच से रिश्वत के पैसे कुछ लोगों को वापस तो करवा दिए, लेकिन इससे वो ग्रामीणों का दुश्मन बन गया। ग्रामीणों ने कहा कि सरपंच ने गुस्सा जाहिर करने के लिए गांव की नल-जल योजना से होने वाली जल सप्लाई बंद कर दी है। अब गांव के लोग 4 हैंडपंप से पीने का पानी लेने को मजबूर हैं और घंटों परेशान हो रहे हैं। बता दें कि खुमान सिंह फिलहाल सरपंच है, लेकिन जब पीएम आवास के लिए लोगों ने पैसे दिए थे तब उसकी पत्नी सरपंच थी। ग्रामीणों ने बताया कि ऐसा कोई काम नहीं जिसके बदले में सरपंच खुमान सिंह रिश्वत न लेता हो। यदि कोई पैसा नहीं देता तो उसका काम नहीं होता है। लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करने वाले लोगों से भी हजारों रुपए की रिश्वत ली जाती है और काम भी समय पर नहीं होते।

सरपंच खुमान सिंह से जब रिश्वत लेने वाले मामले में बात की, तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी से कोई रिश्वत नहीं ली है। जब उनसे पूछा कि 2 दिन पहले विधायक के कहने पर आपने कुछ लोगों के रुपए वापस किए हैं, इस पर खुमान सिंह ने बताया वो रुपए मुझे विधायक ने दिए थे। वहीं जब उनसे कहा कि गांव के इतने सारे लोग एक साथ झूट नहीं बोल सकते, तो उन्होंने कहा कि वो सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने किसी से कोई रुपए नहीं लिए और ना ही किसी को कुछ दिया है। रुपए वापस करने के वायरल हो रहे वीडियो पर उन्होंने कहा आजकल वीडियो में भी कलाकारी हो जाती है। 1 दिन पहले ही

इस गांव के कुछ वीडियो वायरल हुए थे जिसमें ग्रामीण विधायक रामबाई के सामने शिकायत कर रहे थे कि सरपंच ने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कराने के एवज में उनसे हजारों रुपए लिए हैं। शिकायत के बाद गांव पहुंची विधायक ने चौपाल लगाई और पूरे गांव के उन लोगों की सूची बनाई, जिन्होंने सरपंच को रुपए दिए थे। करीब 15 लोग सामने आए, जिनमें से आधा दर्जन लोगों ने गंगाजल उठाकर कसम भी खाई के सरपंच ने रिश्वत ली थी। विधायक ने कुछ लोगों के पैसे वापस करा दिए और कुछ लोगों के पैसे वापस कराने के लिए 2 दिन की मोहलत दी थी। मध्यप्रदेश की बसपा विधायक रामबाई सिंह परिहार एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने चौपाल में सबके सामने सरपंच को लताड़ लगाई और ग्रामीणों से ली गई घूस के रुपए वापस दिलवाए। इसका वीडियो सामने आया है। मामला दमोह जिले में विधायक रामबाई के विधानसभा क्षेत्र पथरिया के घोघरा कला गांव का है। कुछ लोगों ने विधायक से शिकायत की थी, कि सरपंच खुमान सिंह ने प्रधानमंत्री आवास दिलाने के बदले हजारों रुपए लिए, जिसके बाद विधायक खुद गांव गईं और चौपाल लगाई। यहां उन्होंने फोन करके सरपंच पति को भी बुलाया। पहले तो उसने आनाकानी की लेकिन बाद में उसे चौपाल में आना पड़ा।

सशस्त्र सेना झण्डा दिवस पर कलेक्टर ने सभी से सहयोग राशि देने की अपील की

❑सीहोर

सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के अवसर पर जिला पंचायत सभाकक्ष में कलेक्टर प्रवीण सिंह, जिला पंचायत सीईओ हर्ष सिंह सहित सभी जिला अधिकारियों को लेपल पिन लगाकर सहयोग राशि एकत्रित की गई। इस अवसर पर कलेक्टर सिंह ने भारतीय सैनिक कठिन परिस्थितियों में हर समय देश की सीमा की रक्षा करते हैं। देश के भीतर भी सैनिक अपनी अमूल्य सेवाओं के द्वारा बाढ़, भूकंप, तूफान तथा प्राकृतिक विपदाओं के समय सहायता करते हैं। हम भी भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में उदारतापूर्वक आर्थिक सहयोग देकर सेना की त्याग और सेवा की उत्कृष्ट परंपरा के सहयोगी बनने के लिए गौरव का अनुभव कर सकते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि में एकत्रित राशि शहीद सैनिकों के आश्रितों एवं दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के संचालन में उपयोग होती है। उन्होंने सभी से झण्डा दिवस के उपलक्ष्य में दान करने की अपील की। जिला कल्याण संयोजक सूबेदार एसआर कुलकर्णीने झण्डा दिवस के महत्व

के बारे में बताते हुए कहा कि यह दिवस शहीद सैनिकों के सम्मान में उनके परिवारजनों को आर्थिक सहायता पंहुचाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। प्रतीक चिह्नों के प्रतिफलस्वरुप प्राप्त दान राशि शहीद सैनिकों की विधवाओं के इलाज एवं उनके बच्चों की शिक्षा, विवाह आदि के लिए आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। विगत वर्ष 2021-22 में जिले द्वारा लक्ष्य से अधिक राशि संग्रहित करने पर सूबेदार द्वारा समस्त अधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया।

जिले में रासायनिक उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता, सभी सहकारी समितियों में रासायनिक उर्वरक विपणन संघ भंडारित करा रहा

❑सीहोर

वर्तमान में जिले में रबी फसलों की बुआई का कार्य समाप्ति पर है। किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के उप संचालक केके पाण्डेय ने जानकारी दी कि रबी वर्ष 2022-23 हेतु सीहोर जिले के लिए 76500 मे.टन यूरिया, 22000 मे.टन डी.ए.पी., 28000 मे.टन एसएसपी एवं 15000 मे.टन एनपीके की मांग भेजी गयी थी। दिसम्बर माह में किसानों द्वारा गेहूँ की फसल में प्रथम एवं द्वितीय सिंचाई के लिए यूरिया की मांग को देखते हुए 20000 मे.टन यूरिया की मांग शासन से की गई हैं। दिनांक तक 36612 मे.टन यूरिया, एवं 16885 मे.टन डीएपी एवं 5273 मे.टन एनपीके सहकारी क्षेत्र से एवं 20750 मे.टन यूरिया, 6869 मे.टन डीएपी, 1478 मे. टन एनपीके निजी विक्रेताओं द्वारा किसानों को वितरण किया जा चुका है। वर्तमान में विपणन संघ के गोदाम में 403 मे.टन एवं निजी विक्रेताओं के विक्रय केन्द्र पर 1270 मे.टन यूरिया शेष है। इसी प्रकार जिले की 108 सहकारी समितियों में 780 मे.टन यूरिया, 963 मे.टन डीएपी शेष है। सीहोर जिले में कुल 2050 मे. टन यूरिया, 2935 मे.टन डीएपी एवं 1614 मे.टन एनपीके सहकारी एवं निजी विक्रेताओं के पास उपलब्ध हैं। इस प्रकार जिले में पर्याप्त मात्रा में रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता निरंतर बनी हुई हैं। आवश्यकतानुसार सभी सहकारी समितियों में रासायनिक उर्वरक विपणन संघ द्वारा भंडारित कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में कृषकों को उचित दामों में सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायें जा रहे है, जिसमें सभी निजी एवं सहकारी उर्वरक विक्रय केन्द्रो पर राजस्व एवं कृषि विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी समक्ष में खाद वितरण हेतु लगाई गई है।

संविधान संदेश यात्रा ने निकला कैंडल मार्च, अंबेडकर पार्क में हुई जनसभा

❑सीहोर

विभिन्न सामाजिक संगठनों के संयुक्त तत्वाधान एवं संघप्रिय कमलेश दोहरे के नेतृत्व में निकाली जा रही संविधान संदेश यात्रा का मंगलवार को समापन हो गया। मंगलवार सुबह यह यात्रा चांदबड़ से शुरू होकर शेखपुरा, जानपुर बाबड़िया, कोड़िया छीतू, बिजौरी होते हुए सीहोर में प्रवेश किया, जो मंडी, लुनिया चौराहा, तहसील चौराहा पहुंची। इसके बाद तहसील चौराहे से केंडल मार्च निकाला गया, जो नगर मे से होते हुए अंबेडकर पार्क पहुंची, जहां जनसभा हुई। पदयात्रा पर नगर में जगह-जगह पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया। अंबेडकर पार्क में सभी ने बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के महा परिनिर्वाण दिवस पर उनकी प्रतिमा के समक्ष नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पदयात्रा संयोजक कमलेश दोहरे ने सभी को संबोधित करते हुए संविधान में महिलाओं को प्राप्त अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत जानकारी देते हुए बताया कि पूरे देश में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों का विश्लेषण करें तो स्पष्ट है कि अधिकांश मामलों में रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करवाए जाते। चाहे पारिवारिक दबाव हो या सामाजिक दबाव जिसके चलते बहुत सी घटनाएं परिवार की चारदीवारी में ही सिमट कर रह जाती हैं। पंकज शर्मा ने कहा कि विवाहित महिला पर सभी अत्याचार अपराध है, किन्तु इसे व्यवहार में दहेज प्रताड़ना से जोड़ दिया जाता है, जो उचित नहीं है। क्योंकि महिलाएं फौजदारी मुकदमा के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाती और साथ ही उनको घर से निकाले जाने का भी डर रहता है।

पुर्तगाल 16 साल बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचा, स्विट्जरलैंड को 6-1 से हराया

एजेंसी ❑दोहा

कतर में चल रहे फुटबॉल विश्व कप के आखिरी प्री-क्वार्टर फाइनल मैच में पुर्तगाल ने स्विट्जरलैंड को 6-1 से हरा दिया। वह 16 साल के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। पिछली बार 2006 में पुर्तगाल की टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी। वह क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पहला विश्व कप था। अब वह संभवतः अपने आखिरी विश्व कप में खेल रहे हैं और उनकी टीम एक बार फिर से क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी है। पुर्तगाल के लिए मैच के हीरो गोंजालो रामोस रहे। उन्होंने तीन गोल दागे। यह इसक विश्व कप की पहली हैट्रिक है। पुर्तगाल की टीम ने कतर में चल रहे फुटबॉल विश्व कप के आखिरी प्री-क्वार्टर फाइनल में शानदार जीत हासिल की। उसने स्विट्जरलैंड को 6-1 से रौंद दिया। इस जीत के साथ ही पुर्तगाल की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। वह 16 साल के बाद अंतिम-8 में पहुंची है। पिछली बार 2006 में पुर्तगाल की टीम क्वार्टर फाइनल खेली थी। तब वह सेमीफाइनल तक पहुंचने में सफल रही थी। पुर्तगाल की टीम इस बार क्वार्टर फाइनल में मोरक्को के खिलाफ खेलेगी। मोरक्को ने प्री-क्वार्टर फाइनल में स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में हराया। पुर्तगाल के लिए यह जीत इसलिए भी खास है कि उसके छह गोलों में एक भी दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नहीं हैं। रोनाल्डो के बगैर पुर्तगाल ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। इससे टीम का हौसला बढ़ेगा। रोनाल्डो को तो मैच के शुरुआती एकादश में भही नहीं रखा गया था। उन्हें रिप्लेसमेंट के दौरान 73वें मिनट में उतारा गया। पुर्तगाल के लिए मैच में गोंजालो रामोस ने तीन गोल किए। वह पहली बार शुरुआती एकादश में शामिल हुए। उन्हें रोनाल्डो की जगह उतारा गया। उनके ऊपर भारी दबाव था, लेकिन रामोस ने अपने शानदार प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। रामोस ने 17वें, 51वें और 67वें मिनट में गोल किया। उनके अलावा 39 वर्षीय डिफेंडर पेपे ने 33वें, राफर गुएरेरो ने 55वें और राफेल लियायो ने इंजरी टाइम (90+2वें मिनट) में गोल किया। पुर्तगाल ने मैच में गोलों की बारिश कर दी है। उसने छठा गोल भी दाग दिया है। राफेल लिआयो ने इंजरी टाइम (90+2वें मिनट) में किया गोल किया। उनके गोल की बदौलत पुर्तगाल की टीम अब 6-1 से आगे हो गई है। पुर्तगाल ने 67वें मिनट में पांचवां गोल कर दिया। उसके लिए गोंजालो रामोस ने फिर से गोल किया। इस विश्व कप में पहली बार किसी खिलाड़ी ने हैट्रिक गोल दागे हैं। पुर्तगाल इस मैच में अब 5-1 से आगे हो गया है। पुर्तगाल की टीम अपनी आक्रामकता में कमी नहीं ला रही है। वो लगातार दबाव बना रही। इसका फायदा भी उसे मिल रहा है। 55वें मिनट में राफाएल गुरेरो ने गोल कर टीम का स्कोर 4-0 कर दिया। उनके तीन मिनट बाद ही मैनुअल अकांजी ने स्विट्जरलैंड के लिए पहला गोल किया। इस तरह अब स्कोर 4-1 हो गया है। पुर्तगाल की टीम ने तीसरा गोल कर दिया है। गोंजालो रामोस ने 51वें मिनट में स्कोर किया। उन्होंने डिओगो डालोट के शानदार पास को बर्बाद नहीं होने दिया और उसे गोलपोस्ट में डालकर टीम की बढ़त को बढ़ा दिया। पुर्तगाल के 39 वर्षीय डिफेंडर पेपे ने हेडर से शानदार गोल किया। ब्रूनो फर्नांडीस की कॉर्नर किक पर उन्होंने हवा में उछलते हुए गेंद को सिर से मारा और गोलपोस्ट में पहुंचा दिया। पुर्तगाल मैच में अब 2-0 से आगे हो गया है। पेपे नॉकआउट मैचों में गोल करने वाले विश्व कप इतिहास के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। पुर्तगाल ने मैच में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। उसने 17वें मिनट में बढ़त हासिल कर ली। गोंजालो रामोस ने शानदार गोल किया। उन्होंने जोआओ फेलिक्स के पास पर शानदार गोल दागा। गोंजालो रामोस को इस मैच में दिग्गज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जगह उतारा गया है। रोनाल्डो 2008 के बाद टीम में होने के बाद पहली बार किसी मेजर इवेंट (यूरो कप या विश्व कप) में पुर्तगाल के लिए शुरुआती एकादश में नहीं हैं। 31 मैचों का सिलसिला आज टूट गया। पिछली बार भी 14 साल पहले स्विट्जरलैंड के ही खिलाफ शुरुआती एकादश में नहीं थे। पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड के बीच पहले हाफ का खेल शुरू हो गया है। रोनाल्डो के बगैर उतरी पुर्तगाल की टीम मैच के शुरुआत में बढ़त लेना चाहेगी। दूसरी ओर, अपनी मजबूत डिफेंस के लिए प्रसिद्ध स्विट्जरलैंड की टीम उसे कोई मौका नहीं देना चाहेगी।

दूसरे वनडे में चोटिल हुए रोहित शर्मा, अस्पताल ले जाया गया, केएल राहुल ने की कप्तानी

एजेंसी ❑ढाका

भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे वनडे में कप्तान रोहित शर्मा गंभीर रूप से चोटिल हो गए हैं। फील्डिंग के दौरान उनके बाएं अंगूठे में चोट लगी। इसके बाद उन्हें एक्स-रे के लिए ढाका के एक अस्पताल ले जाया गया। बीसीसीआई की मेडिकल टीम रोहित की स्थिति पर नजर रख रही है। हालांकि, वह दूसरी पारी में बैटिंग करेंगे या नहीं इस पर संशय जारी है। बीसीसीआई ने बैटिंग को लेकर कोई अपडेट जारी नहीं किया है। साथ ही रोहित पर तीसरे वनडे में खेलने पर भी संशय है। रोहित की जगह दूसरे वनडे में केएल राहुल कप्तानी कर रहे हैं। रोहित को बांग्लादेश की पारी के दूसरे ओवर में ही चोट लगी। तब वह स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे। इस ओवर में मोहम्मद सिराज गेंदबाजी कर रहे थे। सिराज की गेंद अनामुल हक के बल्ले से लगकर स्लिप में गई। गेंद रोहित के हाथ से लगकर छिटक गई। इस दौरान उनके बाएं हाथ के अंगूठे पर चोट लगी। इसके बाद रोहित दर्द से कराहते दिखे। उन्हें तुरंत मैदान से बाहर ले जाया गया। इसके बाद मेडिकल टीम ने उन्हें स्कैन के लिए अस्पताल ले गई। इसकी अगली ही गेंद पर अनामुल हक आउट हुए। उन्हें सिराज ने एल्बीडब्ल्यू आउट किया। बीसीसीआई ने इसकी पुष्टि की। इस मैच में रोहित की गैरमौजूदगी में राहुल कप्तानी कर रहे हैं। रोहित टी20 वर्ल्ड कप के बाद पहली सीरीज खेल रहे थे। उन्हें न्यूजीलैंड दौरे से आराम दिया गया था। इस साल रोहित की यह सिर्फ तीसरी वनडे सीरीज है। वहीं, भारत ने कुल आठ वनडे सीरीज खेली हैं। रोहित ने पिछली बार इंग्लैंड के खिलाफ जुलाई में वनडे सीरीज खेली थी। तब वह टी20 वर्ल्ड कप पर फोकस कर रहे थे। अब भारत को अगले साल अपने घर में वनडे वर्ल्ड कप खेलना है। ऐसे में रोहित वनडे मैचों पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। इस सीरीज में रोहित के अलावा विराट कोहली और राहुल भी वापसी कर रहे हैं।

गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने को तैयार वीरेंद्र सहवाग का बेटा, दिल्ली की टीम में मिली जगह

एजेंसी ❑नई दिल्ली

भारतीय टीम के साथ दो विश्व कप जीतने वाले वीरेंद्र सहवाग की बल्लेबाजी का हर कोई दीवाना है। अपने करियर में उन्होंने दुनिया के कई दिग्गज गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए थे। पहली गेंद से आक्रमण करने की कला ने सहवाग को खास बनाया था। अब उनकी इसी कला को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी बेटे आर्यवीर सहवाग पर है। आर्यवीर को भी क्रिकेट पसंद है और वह भी पिता की तरह विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं। आर्यवीर ने अपने करियर में आगे बढ़ते हुए एक और सफलता हासिल की है। उनका बीसीसीआई द्वारा आयोजित अंडर-16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए दिल्ली की टीम में हुआ है। 15 साल के आर्यवीर दुनिया को अपनी बल्लेबाजी दिखाने के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया पर उनकी बल्लेबाजी के कई वीडियो हैं। वह पिता की तरह ही स्टांस लेते हैं। उन्हें भी तेजी से बल्लेबाजी करना पसंद है। दिल्ली की अंडर-16 टीम बिहार के सामने हुई, लेकिन प्लेइंग-11 में आर्यवीर को नहीं चुना गया। उन्हें खेलने का मौका भले ही नहीं मिला, लेकिन बड़े स्तर पर उनकी एंट्री जरूर हो गई है।

पाकिस्तानी टीम को मिला भारत का वीजा, वर्ल्ड कप में हो सकेगी शामिल

एजेंसी ❑नई दिल्ली

पाकिस्तान के 34 खिलाड़ियों और अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय से वीजा मंजूरी मिलने के बाद भारत में चल रहे दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान की दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम के भाग लेने का रास्ता साफ हो गया है। इसकी मंजूरी के बाद विदेश मंत्रालय पाकिस्तानी खिलाड़ियों और अधिकारियों को वीजा जारी करेगा ताकि वे 5 से 17 दिसंबर तक होने वाले टूर्नामेंट के लिए भारत की यात्रा कर सकें।

मंत्रालय के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि गृह मंत्रालय ने दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने के लिए 34 पाकिस्तानी खिलाड़ियों और अधिकारियों को वीजा जारी करने की मंजूरी दे दी है। बारह दिन चलने वाले टूर्नामेंट में अब भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, नेपाल और दक्षिण अफ्रीका की टीमें हिस्सा लेंगी। इस टूर्नामेंट के मुकाबले फरीदाबाद, दिल्ली, मुंबई, इंदौर और बेंगलुरु में खेले जाएंगे। भारत अपनी मेजबानी में खिताब का दावेदार है। माना जा रहा है कि फाइनल में उसकी टक्कर पाकिस्तान के साथ हो सकती है। इससे पहले यह बताया गया था कि पाकिस्तानी टीम को वीजा नहीं मिला है। इसकी पुष्टि भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड (सीएबीआई) ने भी की थी। वीजा नहीं मिलने पर पाकिस्तान दृष्टिबाधित क्रिकेट परिषद (पीबीसीसी) ने मंगलवार को बयान जारी करके कहा कि उनकी टीम को भारतीय विदेश मंत्रालय से अनुमति नहीं मिली। पीबीसीसी ने कहा था, ''इस घटना से पाकिस्तान की दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम अधर में लटक गई। इस बात की संभावना थी कि फाइनल में भारत का मुकाबला हमारी टीम से होता। मौजूदा फॉर्म को देखते हुए पाकिस्तान के चैंपियन बनने की दावेदार थी।'' इस प्रतियोगिता का उद्घाटन भारत के पूर्व क्रिकेट युवराज सिंह ने गुरुग्राम में एक कार्यक्रम के दौरान सोमवार को किया था। मंगलवार को मुकाबलों की शुरुआती हुई और फाइनल मैच में 17 दिसंबर को खेला जाएगा।

पीबीसीसी ने कहा था, भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट संघ ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजा देने के लिए अपनी सरकार से गुहार लगाई थी, लेकिन किसी की नहीं सुनी गई। इस भेदभावपूर्ण कार्रवाई के विश्व दृष्टिबाधित क्रिकेट को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे क्योंकि हम विश्व दृष्टिबाधित क्रिकेट से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करेंगे ताकि भारत को भविष्य में अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी न मिले।

मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता, कलाई की चोट के बावजूद 200 किलो वजन उठाया

एजेंसी ❑बोगोटा

भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने कलाई की चोट के बावजूद विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम किया है। उन्होंने इस प्रतियोगिता में कुल 200 किलोग्राम भार उठाया। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता चानू ने 49 किग्रा वर्ग में स्नैच में 87 किग्रा और क्लीन एंड जर्क में 113 किग्रा भार उठाया। चीन की जियांग हुइहुआ ने कुल 206 किग्रा (93+113) भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता, जबकि उनकी हमवतन और टोक्यो ओलंपिक चैंपियन होउ झिहुआ ने 198 किग्रा (89+109) भार उठाकर कांस्य पदक जीता। मुख्य कोच विजय शर्मा ने कहा, हम इस टूर्नामेंट के लिए कोई दबाव नहीं ले रहे थे। यह वह वजन है जिसे मीरा नियमित रूप से उठाती हैं। अब से हम वजन बढ़ाना और सुधार करना शुरू करेंगे। हम (चोट के बारे में) ज्यादा कुछ नहीं कर सके क्योंकि हम विश्व चैंपियनशिप को छोड़ना नहीं चाहते थे। अब हम उनकी कलाई पर ध्यान देंगे क्योंकि हमारे पास अगले टूर्नामेंट से पहले काफी समय है।2017 विश्व चैंपियन चानू को सितंबर में एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान कलाई में चोट लग गई थी। इसके बाद उन्होंने चोट के साथ ही अक्तूबर में राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया था।

गौतम अदाणी का नाम फोर्ब्स की ओर से प्रकाशित एशियाई दानवीरों की सूची के 16 वें संस्करण में टॉप थ्री शामिल किया

गौतम अदाणी एशिया के टॉप तीन दानवीरों में शामिल पिछले वर्ष जून में ने दान की थी 60,000 करोड़ की राशि

एजेंसी ❑ नई दिल्ली

दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों की लिस्ट में शुमार गौतम अदाणी परोपकार के मामले में भी पीछे नहीं हैं। गौतम अदाणी का नाम फोर्ब्स की ओर से प्रकाशित एशियाई दानवीरों की सूची के 16 वें संस्करण में टॉप थ्री शामिल किया है। उनके अलावे इस लिस्ट में एचसीएल टेक्नोलॉजीज के शिव नादर, हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज के अशोक सूटा का नाम शामिल हैं। एशिया के टॉप दानवीरों की यह सूची मंगलवार को जारी की गई।

अदाणी ग्रुप के मुखिया गौतम अदाणी को इस लिस्ट में पिछले वर्ष जून में अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर 60,000 करोड़ रुपये का दान करने के बाद जगह मिली है। इतनी बड़ी राशि परोपकार के लिए खर्च करने की घोषणा कर वे भारत के सबसे बड़े दानवीर बन गए। यह राशि स्वास्थ्य, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट पर खर्च होनी है। इस राशि को अदाणी परिवार के फाउंडेशन की ओर से खर्च की जाएगी, जिसकी स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी।

60 वर्षीय गौतम अदाणी अदाणी ग्रुप के संस्थापक हैं। यह ग्रुप भारत का सबसे बड़ा पोर्ट ऑपरेटर है। यह ग्रुप आधारभूत संरचना, उपभोक्ता वस्तुओं, बिजली उत्पादन व

संचरण व रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़ा है। गौतम अदाणी की संपत्ति में वर्ष 2022 में बड़ा इजाफा हुआ है। वे कुछ समय के लिए दुनिया के दूसरे सबसे धनवान उद्योगपति भी रहे। इस लिस्ट में दूसरा भारतीय नाम शिव नादर का है। पिछले कुछ दशकों के दौरान शिव नादर फाउंडेशन के माध्यम से वे अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा परोपकारी कार्यों पर खर्च कर चुके हैं। इस वर्ष भी वे करीब 11,600 करोड़ रुपये शिव नादर फाउंडेशन को दान कर चुके हैं, जिसकी स्थापना उन्होंने 1994 में की थी। इसका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से लोगों को सशक्त करते हुए एक न्यायसंगत और योग्यता आधारित समाज बनाना था शिव नादर, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के सह-संस्थापक हैं पर उन्होंने आईटी कंपनी के सभी पदों से वर्ष 2021 में इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने शिवनादर फाउंडेशन के माध्यम से कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले शिक्षण संस्थानों जिनमें स्कूल व विश्वविद्यालय शामिल हैं स्थापित करने में मदद की है। इस फाउंडेशन के दूसरे ट्रस्टियों में उनकी पत्नी किरण नादर, बेटी रोशनी नादर और दामाद शिखर मल्होत्रा का नाम है। फोर्ब्स के परोपकारियों की लिस्ट में तीसरे भारतीय का नाम है अशोक सूटा। उन्होंने इस वर्ष 600 करोड़ रुपये का दान किया है। यह राशि उन्होंने अप्रैल 2021 में स्थापित मेडिकल रिसर्च ट्रस्ट के माध्यम से खर्च करने की बात कही थी। इस राशि को बढ़ती उम्र और न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से संबंधित अध्ययन पर खर्च करने की बात कही गई थी। उन्होंने एसकेएन की स्थापना 200 करोड़ रुपये के दान के साथ की थी, आगे चलकर इस राशि को तीन गुना कर दिया गया। फोर्ब्स के अनुसार, इस गैर-रैंक वाली सूची में एशिया-प्रशांत क्षेत्र के व्यक्तिगत रूप से परोपकार करने वाले लोगों को शामिल किया गया है। इसमें वे लोग शामिल हैं जो परोपकार के लिए अपनी कमायी हुई राशि से दान देने के साथ-साथ उसके क्रियान्वयन के लिए अपना समय और ध्यान दें रहे हैं। इस सूची में कंपनियों की ओर सीएसआर के तहत खर्च की जाने वाली राशि शामिल नहीं की गई है।

आरबीआई ने रेपो रेट 0.35 प्रतिशत बढ़ाकर 6.25 प्रतिशत किया, लोन की ईएमआई और बढ़ेगी

एजेंसी ❑ नई दिल्ली

आरबीआई गवर्नर ने तीन दिनों तक चली एमपीसी की बैठक के बाद रेपो रेट को बढ़ाने का एलान किया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 0.35ब्र बढ़ोतरी का एलान किया है। अब आरबीआई की रेपो रेट 5.4ब्र से बढ़कर 6.25ब्र हो गई है। आरबीआई ने लगातार पांचवी बार इसे बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय बैंक ने मई 2022 में रेपो रेट को 40 बेसिस प्वाइंट बढ़ाने की घोषणा के साथ इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद जून, अगस्त और सितंबर महीने में रेपो रेट में 50-50 अंकों की बढ़ोतरी की थी। मई महीने में भी हुई एमपीसी की बैठक में रेपो रेट को 50 बेसिस प्वाइंट बढ़ाकर 4.90ब्र कर दिया गया था। रेपो रेट की बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि अगले चार महीनों में महंगाई दर चार प्रतिशत से ऊपर बने रहने की संभावना है। एमपीसी के छह सदस्यों में से पांच ने रेपो रेट बढ़ाने के फैसले का समर्थन किया है। आरबीआई गवर्नर ने रेपो रेट की घोषणा करते हुए यह भी कहा है कि देश में ग्रामीण मांग में सुधार दिख रहा है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में भी सुधार हुआ है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2023 में जीडीपी ग्रोथ 6.8ब्र रह सकता है। आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा है कि वत्तीय वर्ष

2024 की पहली तिमाही में सीपीआई 5ब्र रह सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति में नरमी के संकेत और वृद्धि को आगे बढ़ाने की आवश्यकता के बीच रिजर्व बैंक बुधवार को अपनी आने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में 35 बीपीएस की वृद्धि का विकल्प चुना है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सोमवार से शुरू हुई मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय बैठक के बाद सात दिसंबर (बुधवार) को अपनी अगली द्विमासिक नीति पेश की है।

जीवन बीमा के प्रीमियम भुगतान पर आयकर में अलग से मिले छूट : तरुण चुघ

एजेंसी ■ नई दिल्ली

बजाज एलियांज लाइफ के प्रबंध निदेशक और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तरुण चुघ ने केंद्रीय बजट 2023 में सरकार से की जा रहीं अपेक्षाओं पर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि आम बजट बड़े पैमाने पर नागरिकों और राष्ट्र की भलाई के लिए नए सुधारों को अमलीजामा पहनाने का अवसर है। जीवन बीमा क्षेत्र के सहभागी के रूप में हमारी प्रमुख दिलचस्पी हमेशा अधिक से अधिक नागरिकों का बीमा करने और यह सुनिश्चित करने में रही है कि लोगों के पास उपयुक्त कवरेज हो। चुघ ने कहा, इस दिशा में हमारी ओर से ओर किए जा रहे समेकित प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा यदि सरकार वर्ष 2023 के आम बजट के दौरान जीवन बीमा के प्रीमियम भुगतान की राशि पर अलग से टैक्स में छूट की सीमा तय करे। उन्होंने कहा कि सरकार से हम यह भी अनुरोध करेंगे कि जीवन बीमा

वार्षिकी या पेंशन उत्पादों को एनपीएस के बराबर लाया जाए। ऐसा विशेष रूप से कर कटौती के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। तरुण चुघ ने कहा कि हमारा मानना है इससे नागरिकों को रिटायरमेंट के बाद प्रभावी तरीके से नियमित आय की योजना बनाने में मदद मिलेगी।

29 करोड़ रुपये जुटाने के लिए हिस्सेदारी बेचेगी अजूनी बायोटेक, 15 को बंद होगा सब्सक्रिप्शन

एजेंसी ■ नई दिल्ली

एक प्रमुख पशु स्वास्थ्य देखभाल और पशुओं के भोजन से जुड़े उत्पाद बनाने वाली कंपनी अजूनी बायोटेक ने अपने राइट्स इश्यू के माध्यम से ?29 करोड़ जुटाने की योजना बनाई है। यह राइट्स इश्यू बुधवार को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। इश्यू के माध्यम से जुटाई गई धनराशि का उपयोग कंपनी अपनी विस्तार योजनाओं, बाजार

बढ़ाने और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। 36 रुपये प्रति शेयर की कीमत वाला राइट्स इश्यू मंगलवार के बंद भाव से 30 फीसदी छूट पर उपलब्ध है। राइट्स इश्यू 15 दिसंबर को बंद होगा। कंपनी ने दिसंबर 2017 में एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर अपना आईपीओ लॉन्च किया था और मई में एनएसई के मुख्य बोर्ड में स्थानांतरित हो गई। डेयरी-कृषि केंद्रित कंपनी 4,83,60,313 पूर्ण चुकता इक्विटी शेयर जारी करेगी।

डॉलर में कमजोरी के असर से सोना 227 रुपये चढ़ा, चांदी 1166 रुपये महंगी हुई

एजेंसी ■ नई दिल्ली

सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोना 227 रुपये बढ़कर 54,386 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। इससे पिछले कारोबारी सेशन में सोना सोना 54,159 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। चांदी भी मंगलवार को 1,166 रुपये प्रति किलोग्राम की उछाल के साथ 67,270 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के रिसर्च एनालिस्ट दिलीप परमार ने कहा, %डॉलर में कमजोरी के बाद सोने की कीमतों में तेजी आई। अंतरराष्ट्रीय य बाजार में सोना सपाट ढंग से 1798.5 डॉलर प्रति औंस के भाव बिक रहा है। वहीं, चांदी 23.08 डॉलर प्रति औंस के भाव पर बिक रही है। मंगलवार के के दिन डॉलर के मुकाबले रुपया 81 पैसे कमजोर होकर 82.62 रुपये पर बंद हुआ, जो 4 नवंबर के बाद का न्यूनतम स्तर है। जानकार उम्मीद करते हैं कि निकट अवधि में केंद्रीय बैंक का हस्तक्षेप अधिक होगा जिससे रुपया 81.80 और 83.00 रुपये के लेवल के बीच कारोबार कर सकता है।

स्विगी में होगी 250 से अधिक कर्मचारियों की छंटनी, 3% कर्मियों को कंपनी कह सकती है बाय-बाय

नई दिल्ली। फूड डिलीवरी स्टार्टअप स्विगी कथित तौर पर इस महीने ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी, कस्टमर सर्विस और सप्लाई चेन में 250 से ज्यादा कर्मचारियों की छंटनी कर रहा है। यह फैसला इसके लगभग तीन से पांच प्रतिशत कार्यबल को प्रभावित कर सकता है। स्विगी की छंटनी उसके मुख्य प्रतिद्वंद्वी जोमैटो की ओर से खराब प्रदर्शन के कारण अपने तीन प्रतिशत कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के कुछ ही महीनों बात आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार छंटनी के फैसले से आपूर्ति श्रृंखला, संचालन, ग्राहक सेवा और तकनीकी भूमिकाओं में तैनात कर्मियों के प्रभावित होने की आशंका है। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि कंपनी अपने कार्यों में एक बहुत छोटी टीम की संरचना चाहती है। इस महीने के अंत में कर्मचारियों के लिए संवेदीकरण कार्यशालाओं की योजना बनाई गई है। उन्होंने पुनर्गठन पर सलाह देने के लिए एक परामर्श फर्म नियुक्त की है। बताया गया है कि अधिकांश छंटनी टेक, इंजीनियरिंग, उत्पाद भूमिकाओं और संचालन से विभागों में हो सकती है हाल ही के एक टाउन हॉल के दौरान स्विगी के मानव संसाधन प्रमुख गिरीश मेनन ने कर्मचारियों को प्रदर्शन आधारित इस छंटनी के बारे में सूचित किया। एक कंसल्टिंग फर्म की मदद से कंपनी ने अपनी टीमों का पुनर्गठन शुरू कर दिया है। स्विगी ने कई अधिकारियों को उपाध्यक्ष के पद पर पदोन्नत करने की भी घोषणा की गई है।

स्वत्वाधिकारी,मुद्रक,प्रकाशक एवं संपादक नागेश नरवरिया द्वारा जय माता प्रिंटर्स म.नं. 1 अमर दाल मिल के पास पेमदीपुरा चिकलोद रोड के पास बापू कालोनी जहांगीराबाद भोपाल मप्र से मुद्रित एवं म.नं. 51 एक्सटेंशन शिवलोक कॉलोनी फेस-3, खजूरी कलां रोड,तह. हुजूर जिला भोपाल से प्रकाशित। संपादक :- नागेश नरवरिया (समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)